दैनिक
इंटीग्रेटेड ट्रेड
डेवलपमेंट सेंटर न्यूज

आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस | 2018 में स्थापित | ITDCNEWS.COM

आरएनआई नं.
MPHIN/2018/77221
डाक पंजीयन नं.
MP/BHOPAL/4-504/2020-22

वर्ष-5 अंक-190, गुरुवार 26 मई 2022, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए

सुविचार

"यदि आपको पहली बार में सफलता नहीं मिलती है, तो फिर से कड़ी मेहनत करें।" - विलियम फैदर

कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ी

सिब्बल ने सपा के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया

कहा- 16 मई को ही पार्टी छोड़ चुका

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी है। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं, ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर गए थे और वे अखिलेश के साथ ही राज्यसभा पहुंचे।

नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वे 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल अभी उप्र से कांग्रेस कोटे से सांसद हैं, लेकिन इस बार उप्र में पार्टी के पास इतने ही विधायक नहीं हैं, जो उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सकें। लिहाजा, सिब्बल के फ्यूचर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल कर उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया।

दिलचस्प बात है कि जब कांग्रेस में सिब्बल के टिकट पर सस्पेंस बरकरार था, उस वक्त 3 बड़ी विपक्षी पार्टियां उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा भेजने को तैयार थीं। उत्तर प्रदेश से सपा, बिहार से राजद और झारखंड से झामुमो सिब्बल को राज्यसभा भेजने का मूड बना चुकी थीं। हालांकि, सिब्बल ने अखिलेश के साथ जाने का मन बनाया।

सपा: सिब्बल को आगे कर आजम को साधने की कोशिश

पहले बात सपा की करते हैं। हाल ही में सपा के कद्दावर नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दिलाने में कपिल सिब्बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेल से निकलने के बाद आजम ने सिब्बल के शान में कई कसीदे भी पढ़े। खास बात ये कि जेल से निकलने के बाद आजम सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से अब तक नहीं मिले हैं। सपा से जुड़े सूत्रों की

मानें तो कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज अखिलेश ने एक तीर से दो निशाना साधने की कवायद की है। इससे एक तो दिल्ली में उन्हें कपिल सिब्बल के तौर पर एक मजबूत चेहरा मिल जाएगा और दूसरा आजम खान को भी साध सकेंगे।

राजद: कानूनी पचड़ों में फंसे लालू परिवार के लिए सिब्बल जरूरी

चारा घोटाला में लालू यादव का केस लड़ रहे कपिल सिब्बल को राजद बिहार से राज्यसभा भेजने का मूड बना रही थी। राजद को बिहार में इस बार राज्यसभा की 2 सीटें मिलनी तय हैं। ऐसे में एक सीट पर पार्टी सिब्बल को उच्च सदन में भेजना चाहती थी। इसकी बड़ी वजह लालू परिवार का कानूनी पचड़ों में फंसना बताया जा रहा है। सिब्बल अभी चारा घोटाला से जुड़े केस में लालू के वकील हैं। इसके अलावा, लालू के ठिकानों पर पिछले दिनों ही छापेमारी की रेड पड़ी है। तेजस्वी यादव और मीसा भारती पर भी एक मामले में केस दर्ज है। ऐसे में राजद कपिल सिब्बल को साथ जोड़कर लीगल तौर पर मजबूत होने की तैयारी में थी। इससे पहले 2016 में लालू यादव वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को भी राज्यसभा भेज चुके हैं।

झामुमो: खतरे में पड़ी सीएम कुर्सी बचाने में जुटे हेमंत

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कुछ दिनों से मुश्किलों में घिरे हुए हैं। उन पर मंत्री रहते माइंसं की लीज लेने का आरोप है। इस मामले में सदस्यता रद्द करने का केस चुनाव आयोग के पास विचाराधीन है। इसके साथ ही यह मामला कोर्ट में भी गया है। कोर्ट में सोरेन की तरफ से इस मामले की पैरवी कपिल सिब्बल ही कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, झामुमो अपने कोटे से सिब्बल को राज्यसभा भेजने का मन बना चुकी थी। झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें सत्ताधारी दल को एक सीटें मिलना तय माना जा रहा है। वहीं एक सीट पर फाइट होने की संभावना है।

उप्र, पंजाब समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक इंटरव्यू में सिब्बल ने कहा कि घर की कांग्रेस नहीं अब सबकी कांग्रेस होगी। उन्होंने कहा- कांग्रेस में अध्यक्ष ना होते हुए भी फैसला राहुल गांधी ले रहे हैं, जबकि हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। राहुल के रहते कांग्रेस कई चुनाव हार चुकी है, ऐसे में नए लोगों को नेतृत्व दिया जाना चाहिए।

पीएम मोदी आज चेन्नई में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बने घरों का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को चेन्नई में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बने 1152 घरों का उद्घाटन करेंगे। पीएम

आवास योजना-शहरी के तहत 116 करोड़ रुपये की लागत इन घरों का निर्माण किया गया है। इन घरों को बनाने के लिए नवीनतम तकनीक, सामग्री और प्रक्रियाओं को उपयोग में लाया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इस परियोजना में प्रीकास्ट कंक्रीट निर्माण प्रणाली का इस्तेमाल किया है। अभी तक इस प्रणाली का इस्तेमाल यूएस और फिनलैंड सरीखे देशों में किया जाता था। प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी, 2021 को पूरे देश में कुल छह जगहों पर लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम ड्रोन आधारित निगरानी के माध्यम से परियोजना की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं।

अखिलेश ने बोला योगी सरकार पर हमला

लखनऊ। यूपी विधानसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज तक के इतिहास में अगर कोई सबसे विफल सरकार हुई है तो वह यह सरकार है। प्रदेश में अराजकता का माहौल, ध्वस्त कानून व्यवस्था, सामूहिक बालात्कार, नफरत, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली, विकास रोकने वाली, महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचाने वाली यह सरकार है।

संजय राउत ने तमिलनाडु सरकार पर उठाए सवाल

मुंबई। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के अपराधी से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मुलाकात पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की राजनीति क्या है सबको मालूम है। राजीव गांधी इस देश के नेता थे, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। तमिलनाडु में ही उनकी हत्या हुई थी। राज्य के मुख्यमंत्री अगर उनके हत्यारों को इस तरह से सम्मानित करते हैं तो मुझे लगता है कि वो हमारी संस्कृति और नैतिकता नहीं है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया झीरम घाटी शहीद मेमोरियल का लोकार्पण

जगदलपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में झीरम घाटी शहीद मेमोरियल का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने झीरम घाटी हमले में शहीद हुए कांग्रेस के नेताओं और जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही यहां पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा भी फहराया है। बताया जा रहा है कि तिरंगा यहां सालभर लहराता रहेगा। झीरम हमले में शहीद हुए नेताओं और जवानों के परिजनों से भी सीएम ने मुलाकात की। इस मौके पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बस्तर सांसद दीपक बैज समेत कांग्रेस के अन्य नेता भी उपस्थित थे। सुकमा से जगदलपुर आ रहे नेताओं के काफिले पर हुए हमले में मारे गए सभी शहीदों की प्रतिमाओं का अनावरण सीएम ने किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि झीरम के शहीदों को नमन करते हुए मैं जगदलपुर में बनाए गए झीरम घाटी शहीद स्मारक को लोकार्पित कर रहा हूं। झीरम घाटी की हृदयविदारक घटना में शहीदों को नमन करता हूं। सरकार शहीद परिवारों के सुख-दुख में हमेशा सभी के साथ है। हम सभी शहीदों के परिवारों के साथ परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, झीरम घाटी की घटना के 9 साल हो गए हैं। इस घटना में हमने अपने कई नेताओं और जवानों को खोया है। इन 9 सालों में हमने भरसक कोशिश की कि इस घटना के सही तथ्य सामने आए। सभी जानते हैं कि यह घटना राजनीतिक षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र को उजागर करने की हमने बहुत कोशिश की। एनआईए की जांच भी संतोषजनक नहीं। एनआईए से अलग यहां की राज्य पुलिस जब जांच करने तत्पर हुई, तो उसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट गई।

अमेरिका के स्कूल में 18 साल के स्टूडेंट ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

19 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत, राष्ट्रपति जो बाइडन ने दी कड़ी चेतावनी, चार दिन का राष्ट्रीय शोक

टेक्सास, एजेंसी। अमेरिका के टेक्सस में दिल को झकझोर देने वाली घटना घटी है। दक्षिण टेक्सास के राब प्राथमिक विद्यालय में गोलीबारी में 19 बच्चों और 3 अन्य की मौत हो गई। शूटर की उम्र 18 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान शूटर मारा जा चुका है। यह जानकारी टेक्सस के गवर्नर (राज्यपाल) ग्रेग एबाट ने दी है। गवर्नर के इस घटना को टेक्सस के इतिहास में गोलीबारी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक बताा है।

बता दें कि 2012 सैंडी हुक प्राथमिक विद्यालय की शूटिंग के बाद यह सबसे घातक स्कूल शूटिंग है। यह घटना उवाल्डे, टेक्सस में घटी है, जो एक छोटा शहर है, जिसमें 20,000 से अधिक लोग नहीं रहते हैं। हमलावर का नाम सल्वाडोर बताया जा रहा है। राज्यपाल एबाट ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि बंदूकधारी एक बंदूक और राइफल लेकर उवालदे के राब एलीमेंट्री स्कूल में दाखिल हुआ था। शूटर उस समुदाय का निवासी था जो सैन एंटोनियो से लगभग 85 मील (135 किलोमीटर) पश्चिम में है। बता दें कि राब एलीमेंट्री स्कूल में सिर्फ 600 से कम छात्रों का नामांकन है। टेक्सस में सामूहिक गोलीबारी पर, गवर्नर ग्रेग एबाट ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि टेक्सस के सभी लोग इस मूर्खतापूर्ण अपराध के पीड़ितों

और उवाल्डे समुदाय के लिए शोक मना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सेसिलिया (एबाट की पत्नी) और वो इस भीषण नुकसान पर शोक व्यक्त करते हैं और टेक्सस के सभी लोग एक साथ मिलकर पीड़ितों के सहयोग के लिए आगे आएं। उन्होंने आगे कहा, मैं सभी सुरक्षाकर्मी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अंततः राब एलीमेंट्री स्कूल को सुरक्षित करने के लिए काम किया। बता दें कि राष्ट्र ध्वज आधा फहराने का कार्य पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के रूप में किया जा रहा है। इस घटना पर व्हाइट हाउस की नई प्रेस सचिव कारीन जीन-पियरे ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडन को टेक्सस में स्कूल में हुई गोलीबारी की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने ट्वीट किया, राष्ट्रपति बाइडन को टेक्सस में प्राथमिक स्कूल में गोलीबारी की भयावह खबर के बारे में जानकारी दी गई है और जानकारी उपलब्ध होने पर उन्हें नियमित रूप से जानकारी दी जाती रहेगी।

बाइडन ने दिया भावुक संदेश

गोलीबारी के बाद जो बाइडन ने हथियारों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर भावुक संदेश दिया है। संदेश देते हुए उन्होंने कहा, भागवान के नाम पर हम कब बंदूख लाबी के सामने खड़े होंगे। राष्ट्रपति ने दुख जताते हुए कहा कि अब जो बच्चे इस गोलीबारी में मारे गए हैं उनके मां-बाप अब कभी भी अपने औलाद को नहीं देख पाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह की सरेआम और वीभत्सव गोलीबारी शायद ही कहीं दुनिया में होती होंगी। बाइडन ने कहा कि वे हथियार पर लगाने वाले प्रतिबंध को लेकर काफी चिंतित हो चुके हैं और अब कोई न कोई कदम उठाने की जरूरत है। इससे पहले अमेरिका की उप-राष्ट्रपति ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि ऐसे घटनाओं ने हमारे दिलों को पूरी तरह तोड़ दिया है, लेकिन हमारी पीड़ा उन मां-बाप की तुलना में कुछ नहीं है, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। हमें कड़े कदम उठाने की जरूरत है। बता दें कि राष्ट्रपति बाइडन ने टेक्सास के राज्यपाल से बातकर हर संभव मदद देने की बात कही है।

आधा फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज

जो बाइडन ने गोलीबारी की घटना पर शोक जताते हुए व्हाइट हाउस और दूसरे सार्वजनिक भवनों में अमेरिकी राष्ट्र ध्वज को 28 मई, सूर्यास्त तक आधे फहराने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि अमेरिका के सभी दूतावासों, विरासतों, कांसुलर कार्यालयों और सामूहिक कार्यालयों में अमेरिकी राष्ट्र ध्वज को 28 मई, सूर्यास्त तक आधे फहराए जाएंगे।

ज्ञानवापी मस्जिद केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ ट्रांसफर, 30 मई को होगी अगली सुनवाई

वाराणसी, एजेंसी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में सिविल जज (सीनियर डिविजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से मुकदमा दाखिल किया गया है। यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह ने दाखिल किया है। इस दौरान हिंदू पक्ष की ओर से वाद दाखिल करने वाले लोग भी शामिल रहें। इस मामले में दोपहर दो बजे के बाद सुनवाई हुई तो ज्ञानवापी केस सिविल जज ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। सिविल जज रवि दिवाकर ने नई याचिका को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा है जिसकी सुनवाई के लिए 30 मई नई तिथि मुकर्रर कर दी गई है। अब इस केस की सुनवाई जज महेंद्र पांडेय करेंगे। दूसरी ओर ज्ञानवापी मामले को लेकर चल रही सुनवाई को देखते हुए ज्ञानवापी परिसर और काशी विश्वनाथ परिसर ही नहीं, बल्कि कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। सुरक्षा कड़ी होने के साथ ही हर आने जाने वाले पर नजर रखने के साथ ही संबंधित जगहों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही थी। इस बाबत पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रहे। बुधवार को सुबह से लेकर दोपहर तक सुरक्षा व?यवस?था कड़ी रहने से लोगों की आवाजाही भी कम रही।

वैदिक सनातन संघ के जीतेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरन सिंह की याचिका में मांग की गई है कि ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। भगवान आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योर्तिलिंग जो अब सबके सामने प्रकट हो चुके हैं उनकी तत्काल पूजा- पाठ शुरू करने की इजाजत दी जाए।

भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए मंत्री अरविंद भदौरिया

भिंड। बुधवार को भिण्ड जिले के भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री गाविंद सिंह राजपूत के साथ सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी सम्मिलित हुए। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों से संबंधित चर्चा की। बैठक में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष व सांसद श्रीमति संध्या राय, प्रदेश मंत्री केशव भदौरिया, जिलाध्यक्ष नाथूसिंह गुर्जर, जिला महामंत्री धीर सिंह भदौरिया, कमल शर्मा, धर्म सिंह जाटव, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य संजीव कांकर, अवधेश सिंह कुशवाह, देवेन्द्र नरवरिया सहित कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे।

राहुल गांधी को भारत जोड़ो, नही कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए: डॉ मिश्रा

भोपाल। कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा व उस यात्रा के लिए बनी समिति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को शामिल करने पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में देश पहले से ही मजबूती से जुड़ा हुआ है।

उसे जोड़ने की चिंता करने की जरूरत नही है। राहुल गांधी को तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए जो कबीलों की तरह बंटी हुई है। गृह मंत्री डॉ मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी जी दरअसल कांग्रेस जोड़ो यात्रा ही निकालना चाहते है, बस नाम दे दिया भारत जोड़ो यात्रा। देश तो पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के सक्षम हाथों में है, पूरी दुनिया मे भारत का डंका बज रहा है। ऐसा कोई महीना नही जाता जब दुनिया के देशों का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत नही आता हो। यह सब कांग्रेस को भी पता है। इसलिए वह भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल रही है। जरूरी भी है क्योंकि कांग्रेस ही इस समय पूरी तरह टूटी व बिखरी हुई है।

कमलनाथ जी आखिर दिग्विजय सिंह को प्रदेश से दूर करने में रहे सफल

गृह मंत्री ने कहा कि जहाँ तक इस यात्रा के लिए बनी समिति में दिग्विजय सिंह को शामिल करने की है तो इससे ज्यादा खुशी कमलनाथ जी को ही हुई होगी। कमलनाथ जी किसी भी तरह दिग्विजय सिंह को प्रदेश से दूर करना चाहते थे उनकी यह मंशा आज पूरी हो गई है।

निकाय चुनाव: गृह मंत्री का बड़ा बयान-अब तक कोई अध्यादेश राजभवन नहीं भेजा गया है

मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। मध्यप्रदेश में महापौर, नपाध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्षों को पार्षद चुनेंगे या जनता इसका अबतक फैसला नहीं हो पाया है, हालांकि शिवराज सरकार द्वारा इसको लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी है, इसी बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। आज मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव से जुड़ा कोई भी अध्यादेश अब तक राजभवन नहीं भेजा गया है। बता दे कि शिवराज सरकार ने पहले अध्यादेश राज्यपाल को भेजा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे वापस बुला लिया था। दरअसल, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आगामी चुनाव में जनता ही महापौर व नपा अध्यक्ष का चुनाव करेगी, इसके लिए शिवराज सरकार ने एक बार फिर अध्यादेश को राजभवन भेजा है। इसके तहत नगर निगमों में महापौर, नगर पालिका एवं नगर परिषदों में अध्यक्ष पद के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएंगे, यानी सभी का चुनाव सीधे जनता करेगी। यह निर्णय मंगलवार देर शाम भाजपा दफ्तर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ हुई बैठक के बाद लिया, लेकिन गृह मंत्री ने इससे इंकार कर दिया है। बता दें किहाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह का भी बयान सामने आया था कि नगरीय निकायों के चुनाव को देखते हुए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला लिया है। कमलनाथ सरकार के फैसले को बदला जाएगा। इसके तहत महापौर नगर पालिका और नगर परिषदों में अध्यक्ष जनता चुनेगी। पुराने नियमों से चुनाव होंगे। एक शहर में एक ही महापौर होगा। महापौर और अध्यक्ष शहर का प्रतिनिधित्व करता है जनता से निर्वाचित होना चाहिए। हम अध्यादेश लायेंगे, इसको लेकर आयुक्त को सूचित कर दिया गया है।

न्यूज ब्रीफ

उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर स्वास्थ्य संस्थाओं में नागरिकों का भरोसा बढ़ाएँ

भोपाल। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में संसाधनों को बढ़ाया गया है। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रति आम नागरिकों में भरोसा बढ़ाये। आम नागरिकों का शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में यह भरोसा होना चाहिये कि उन्हें निजी अस्पतालों से अच्छा इलाज मिलता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने प्रदेश के जिला अस्पतालों से जुड़ कर विभागीय वर्चुअल समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, स्वास्थ्य संचालक श्री अनुराग चौधरी और श्री दिनेश श्रीवास्तव भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि सभी जिला और सिविल अस्पतालों में संसाधनों का विस्तार किया गया है। अस्पतालों में पैथालॉजी जाँच के लिये नई मशीनें लगाई गई हैं। सोनोग्राफी, डिजिटल एक्स-रे मशीन और सीटी स्केन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। अस्पतालों में स्टॉफ की भी नियुक्ति की गई है। मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ और अन्य सुविधाएँ दी जा रही हैं। इन सबके होते हुए यदि किसी बात की कमी है, तो वह हमारी इच्छा-शक्ति की है। कोरोना काल में शासकीय अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरा-मेडिकल स्टॉफ द्वारा बेहतर सेवाएँ देने से आम नागरिकों का उन पर भरोसा बढ़ा है। इसे और अधिक मजबूत करने की जरूरत है।

स्वास्थ्य संस्थाओं का बदलेगा स्वरूप

प्रदेश के सभी जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप स्वास्थ्य केन्द्र को बेहतर बनाने के लिये संस्था प्रमुख को बजट और अधिकार दिये जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि सभी अस्पतालों के प्रमुखों को अस्पताल के सिविल, इलेक्ट्रिकल और इंटीरियर के संधारण और मरम्मत के लिये अधिकार एवं बजट उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रमुख अस्पताल में संधारण और रख-रखाव के जरूरी कामों को आसानी से कर सकें, इसके लिये अनावश्यक प्रक्रियाओं से भी मुक्त रखा जायेगा। इसमें स्वास्थ्य संस्था में रंगाई-पुताई से लेकर बिजली फिटिंग और अन्य छोटे-मोटे मरम्मत के कार्य शामिल होंगे। स्वास्थ्य संस्था प्रमुखों को अब किन्तु-परंतु का कोई बहाना नहीं रहेगा।

आँगनवाड़ियों के लिए सामग्री एकत्रीकरण, जन-भागीदारी का अद्भुत प्रयोग रहा : मुख्यमंत्री चौहान

- समाज के सहयोग से कुपोषण एक साल में किया जा सकता है समाप्त
- जो परिवार उचित मूल्य दुकान से राशन नहीं ले रहे, उनके नाम हटाकर जरूरतमंदों को जोड़े
- भ्रष्टाचारियों और राशन चोरों को भेजें जेल
- प्रदेशवासियों को सुशासन देने के संकल्प का क्रियान्वयन है, प्रातः कालीन समीक्षा-सत्र
- कल्याण योजनाओं का दिया जाएगा शत-प्रतिशत लाभ
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रातः 6.30 बजे की रायसेन और नरसिंहपुर जिले की समीक्षा
- मण्डीदीप में पेयजल की स्थिति में तत्काल सुधार के लिए पी.एस नगरीय विकास को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रातः 6:30 बजे रायसेन जिले की विकास गतिविधियों की समीक्षा की।

भोपाल

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कुपोषण की समस्या वर्षों से रही है। इस दिशा में निरंतर प्रयास भी किए जाते रहे हैं। परन्तु मेरा यह मानना है कि बिना समाज के सहयोग से प्रदेश में कुपोषण को दूर नहीं किया जा सकता है। प्रदेश के कई स्थानों पर गौरव दिवस का आयोजन प्रारंभ किया गया, जिसमें लोगों ने आँगनवाड़ी के लिए भी सामग्री दी। मैं स्वयं 24 मई को भोपाल में आँगनवाडियों के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से सड़कों पर निकला। कुल 800 मीटर की यात्रा में जनता की ओर से दस ट्रक सामग्री और 2 करोड़ रूपये के चेक प्रदान किए गए। कई लोगों ने आँगनवाड़ियों की जिम्मेदारी लेने का संकल्प लिया। यह जन-भागीदारी का अद्भुत प्रयोग रहा है। सामाजिक कार्यों और लोगों का जीवन स्तर उठाने में सहयोग के लिए सभी तत्पर हैं। हमें जन-कल्याणकारी योजनाओं और विकास गतिविधियों में जन-भागीदारी को अभियान का रूप देना होगा। किसान अनाज दें, लोग अपने जन्म-दिवस, वर्षगाँठ, परिजन के पुण्य-स्मरण में आँगनवाड़ियों की गतिविधियों में योगदान दें। जन-अभियान परिषद, दीनदयाल अंत्योदय समिति और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाए। मेरा यह विश्वास है कि जन-भागीदारी से एक साल में प्रदेश में कुपोषण समाप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज प्रातः 6:30 बजे रायसेन और नरसिंहपुर जिले की विकास गतिविधियों, जन-कल्याणकारी योजनाओं और कानून-व्यवस्था की स्थिति की वर्चुअल समीक्षा कर रहे थे। निवास कार्यालय से हुई बैठक में रायसेन जिले के प्रभारी एवं सहकारिता मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया, नरसिंहपुर के प्रभारी एवं वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह वर्चुअली जुड़े। रायसेन से स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री श्री रामपाल सिंह तथा कलेक्टर श्री अरविंद कुमार दुबे, नरसिंहपुर से पूर्व मंत्री श्री जालम सिंह पटेल, कलेक्टर श्री रोहित सिंह सहित दोनों जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दोनों जिलों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति, राशन वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना में जारी कार्यों, स्वास्थ्य व्यवस्था, आँगनवाड़ियों के संचालन, अमृत सरोवर योजना तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति एवं अपराधियों और माफियाओं से भूमि मुक्त कराने के लिए जारी गतिविधियों की समीक्षा की।

रायसेन जिले की समीक्षा

जिले की 90 प्रतिशत आबादी कृषि गतिविधियों पर आधारित है। सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए अभियान आरंभ किया गया। ब्याज की दर बढ़ाने से 60 करोड़ रूपये डिपॉजिट प्राप्त हुआ। वसूली के लिए विशेष अभियान आरंभ किया गया। जिले में 110 करोड़ रूपये का फार्टिलाइजर बाँटा गया है। जिले में कुल 11 नगरीय निकाय हैं, जिसमें से 10 में पेयजल की स्थिति सामान्य है। मण्डीदीप में दो दिन में एक बार पानी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कार्य को गति नहीं देने पर ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट किया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल स्तर कम हो जाने से 202 हेंडपंप में राइजर पाइप बढ़ाए गए हैं। कुल 29 नल-जल योजनाओं में पानी की समस्या है, जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जिले में जल जीवन मिशन की 542 योजनाओं में से 134 में कार्य पूर्ण हो गया है। जल कर संग्रहण और नल-जल योजनाओं के संधारण में महिला स्व-सहायता समूहों को जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोगों को स्वेच्छा से जल कर देने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है।

पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने मंत्रालय में लेबनान में भारत के राजदूत डॉ. सोहेल एजाज खान से सौजन्य भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नीम और बरगद के पौधे रोपे

भोपाल

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी उद्यान में नीम और बरगद के पौधे रोपे। अन्नशेष फाउंडेशन की सुश्री श्रेया जैन, सुश्री कीर्ति राजपूत, सुश्री रूचि समुंद्र, श्री अभिषेक साहू तथा श्री प्रांशु राय ने भी पौध-रोपण किया। फाउंडेशन विगत 3 वर्षों से जरूरतमंदों को भोजन, स्वच्छता, पौध-रोपण और बच्चों की सहायता के लिए काम कर रही है। भोपाल सहित जबलपुर, साँची, उज्जैन और रीवा में इनके केन्द्र संचालित हैं। कोरोना काल में भी जरूरतमंद लोगों की मदद की। आज लगाए गए बरगद के पेड़ को वट वृक्ष या बड़ भी कहा जाता है। इसका धार्मिक महत्व है और आयुर्वेद में भी इसका उपयोग होता है। एंटीबायोटिक तत्वों से भरपूर नीम को सर्वोच्च औषधि के रूप में जाना जाता है।

कुसुम-अ योजना में बैंक गारंटी 5 लाख से घटकर एक लाख रूपये हुई

- मंत्री श्री डंग ने कृषकों को वितरित किए लेटर ऑफ अवार्ड
- विकासकों और पॉवर मैंनेजमेंट कंपनी के बीच हुआ विक्रय-क्रय अनुबंध

भोपाल

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (कुसुम-%अ%) में अब बैंक गारंटी 5 लाख रूपये प्रति मेगावॉट से घटाकर एक लाख रूपये कर दी गई है। श्री डंग ने यह जानकारी आज ऊर्जा भवन में कुसुम-%अ% के 71 कृषकों को लेटर ऑफ अवार्ड वितरित करते हुए दी। कार्यक्रम में 6 विकासकों द्वारा मध्यप्रदेश पावर मैंनेजमेंट कंपनी के मध्य विक्रय-क्रय अनुबंध (पीपीए) का भी अदान-प्रदान किया गया। ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिर्राज दंडोतिया, प्रमुख सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री संजय दुबे, प्रबंध संचालक श्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश के कुसुम-%अ% योजना के चयनित किसान, विकासक, बैंक अधिकारी और संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

जल्दी ही लगेंगे खेतों पर एक हजार सोलर पंप

मंत्री श्री डंग ने कहा कि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में एक हजार ऐसे किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगाने का काम प्राथमिकता से शुरू किया जा रहा है, जहाँ विद्युत की उपलब्धता नहीं है। प्रदेश में 50 हजार किसानों के खेत पर सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इससे बिजली-डीजल का खर्चा बचने के साथ 8 घंटे बिजली मिलने से किसानों के अन्य कार्य भी सरलतापूर्वक पूरे हो जायेंगे।

पर्यावरण-संरक्षण के साथ किसान बनेंगे उद्यमी

विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई देते हुए मंत्री श्री डंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के पर्यावरण-संरक्षण के साथ किसानों की आय दोगुनी करने के सपने को साकार करने में आप सभी लोगों के कठोर श्रम का योगदान है। श्री डंग ने कहा किसानों की आय को बढ़ाने वाली कुसुम योजना से किसान अब उद्यमी भी बनेंगे। ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिर्राज दंडोतिया ने कहा कि प्रदेश का किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी बनने जा रहा है। प्रमुख सचिव श्री दुबे ने किसानों से अपील कि की वे अच्छी गुणवत्ता का पैनल और इंवर्टर लें जिससे निर्बाध रूप से अच्छी ऊर्जा का उत्पादन होगा। उन्होंने कृषकों को विभाग से उनके द्वारा उत्पादित ऊर्जा के लिए हर माह भुगतान और तकनीकी सहयोग का अश्वासन दिया।

गंगाईवीर का गौ-सदन गौवंश वन्य-विहार के रूप में होगा विकसित

स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने किया भूमि-पूजन

भोपाल

मध्यप्रदेश गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने जबलपुर के गंगाईवीर वन क्षेत्र में विकसित होने वाले गौवंश वन्य-विहार का भूमि-पूजन किया। गौवंश विहार के लिये 3 ग्राम पंचायतों दशरथपुर, कोलमुही और टेहरीकला की भूमि का चयन किया गया है। गौवंश विहार में निराश्रित, भटके हुए और बीमार गौवंश को संरक्षण मिलेगा और आहार लाभ के साथ स्वच्छंद विचरण भी कर सकेंगे। स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार प्रदेश के बन्द गौ-सदनों को गौवंश वन्य-विहार के रूप में विकसित कर गौवंश के रहने और खाने की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1916 में बने 8 गौ-सदनों को वर्ष 2000 में समाप्त किया गया था। वन क्षेत्र में बनें गौ-सदनों में गौ माता के स्वाभाविक हक की 6700 एकड़ भूमि है। भूमि को लक्ष्य कर गौ-संरक्षण का रोडमेप बनाकर हम कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नये स्वरूप में विकसित होकर गौवंश वन्य-विहार, गौ-संरक्षण की दिशा में कारगर सिद्ध होंगे। उचित देखभाल होने के कारण गौ-वंश सड़कों की ओर रूख नहीं करेंगे। विधायक श्रीमती नंदिनी मरावी, जन-अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. जितेन्द्र जामदार, प्रशासनिक और पशुपालन विभाग के अधिकारी, जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

दैनिक इंटीग्रेटेड ट्रेड
डेवलपमेंट सेंटर न्यूज
मध्य भारत का एक विश्वसनीय दैनिक
98 26 22 00 22
अर्थव्यवस्था, शिक्षा,
नियोजन, उद्भव,
पर्यावरण, मनोरंजन.
आपकी बात
आपके साथ
We Are One- Veer
PRESS ITDC ITDC NEWS

संपादकीय

5जी की ओर

भारत 5जी प्रौद्योगिकी की ओर कदम बढ़ा चुका है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में स्थापित एक परीक्षण नेटवर्क पर पहली 5जी कॉल की, तब भारत ने संचार के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। यह परीक्षण सफल रहा, यानी आने वाले समय में भारत में 5जी सेवाओं का विस्तार तेजी से होगा। सबसे अच्छी बात है कि इस तकनीक के विकास में हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का ही सर्वाधिक योगदान है। तकनीकी विकास में जितनी तेजी आएगी, भारत के विकास को उतना ही बल मिलेगा। वैसे भी यह ध्यान देने की बात है कि इस तकनीक में भारत दुनिया में विकसित देशों से पीछे चल रहा है। कुछ देशों में साल 2019 से ही 5जी की शुरुआत हो चुकी है। एक अनुमान है कि साल 2025 तक दुनिया में एक अरब से ज्यादा लोग 5जी का इस्तेमाल करने लगेंगे, लेकिन तब तक 6जी की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी।

दरअसल, कोरोना महामारी की वजह से 5जी तकनीक के मामले में देरी हुई है। पिछले साल ही यह घोषणा हुई थी कि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 के अप्रैल से मई के आसपास होगी। लेकिन इस काम में कुछ देरी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस साल की शुरुआत में बजट पेश करते हुए स्पेक्ट्रम नीलामी की बात कही थी। आशा है कि बहुत जल्दी ही पांचवीं पीढ़ी की इन सेवाओं के लिए नीलामी का आयोजन होगा और कुछ ही महीनों में 5जी सेवा आम लोगों के हाथों में पहुंच जाएगी। भारत इस कोशिश में है कि इन सेवाओं के मामले में किसी भी देश पर हमारी निर्भरता न रहे और तकनीक हर स्तर पर स्वदेश आधारित हो। आज सूचनाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। तकनीक की सुदृढ़ता से ही भारत संचार को मजबूती मिलने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग अगले सप्ताह 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में पेश करेगा और सेवाओं की शुरुआत अगस्त या सितंबर से शुरू हो जाएगी। लोग तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्दी यह सुविधा हासिल हो। अच्छी बात है कि अभी संचार कंपनियां अपने स्तर पर 5जी का परीक्षण कर रही हैं और वे अपने स्तर पर सेवा देने के लिए लगभग तैयार हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल टेलीफोन सेवा ने लंबा और शानदार सफर तय किया है। 1970 के दशक के अंत में जापान में 1जी लॉन्च किया गया था। यह मोबाइल दूरसंचार तकनीक की पहली पीढ़ी थी, जो केवल वॉयस कॉल की सुविधा देती थी। साल 1991 में 2जी की शुरुआत के साथ तकनीक ने इतिहास रचने की शुरुआत की। दूसरी पीढ़ी में तकनीक पूरी तरह से डिजिटल हो गई। लोग फोन को लेकर घूमने लगे। फोन पर बातचीत करने के लिए एक जगह रहने की मजबूरी खत्म हो गई। वास्तव में, भारत में 2जी आज भी सबसे लोकप्रिय और सबसे उपयोगी बना हुआ है। जबकि 4जी की सेवा से एक बड़ी आबादी है, जो वंचित है। दूरसंचार कंपनियों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक ही तरह की सेवा देश में सभी ग्राहकों को मिले। ऐसा न हो कि 2जी सेवा भी चलती रहे और देश का एक वर्ग 5जी पर आ जाए। कुछ कंपनियों ने 2जी से आगे बढ़ने के लिए अभियान छेड़ रखा है, लेकिन अभी भी 20 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हमें सुधार की दिशा में ज्यादा तेजी से बढ़ना चाहिए और सेवाओं को किफायती रखने की कोशिश भी जारी रहनी चाहिए।

खतरे में जैव विविधता

अप्रभावित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से अधिकांश इलाके उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, जहां मानव उपस्थिति कम रही है, लेकिन अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ये जैव विविधता से समृद्ध नहीं थे। धरती पर जैव विविधता के अस्तित्व पर मंडराते संकट को लेकर शोधकर्ताओं का कहना है कि अधिकांश प्रजातियां मानव शिकार के कारण लुप्त हुई हैं, जबकि कुछ अन्य कारणों में दूसरे जानवरों का हमला और बीमारियां शामिल हैं। हालांकि उपग्रह से मिली तस्वीरों के आधार पर शोधकर्ताओं का मानना है कि धरती के ऐसे बीस फीसद हिस्से की जैव विविधता को बचाया जा सकता है जहां अभी पांच या उससे कम बड़े जानवर ही गायब हुए हैं। लेकिन इसके लिए मानव प्रभाव से अछूते क्षेत्रों में कुछ प्रजातियों की बसावट बढ़ानी होगी, ताकि पारिस्थितिकीय तंत्र में असंतुलन पैदा न हो।

(योगेश कुमार गोयल)

विकास के नाम पर यदि वनों की कटाई जारी रही और जीव-जंतुओं और पक्षियों से उनके आवास छीने जाते रहे तो ये प्रजातियां धरती से एक-एक कर लुप्त होती जाएंगी और भविष्य में इससे पैदा होने वाली भयावह समस्याओं और खतरों का सामना समस्त मानव जाति को ही करना होगा।

बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, शिकार और वृक्षों की कटाई जैसी गतिविधियों से धरती पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। प्रदूषित वातावरण और प्रकृति के बदलते मिजाज के कारण जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। कई प्रजातियां तेजी से लुप्त होती जा रही हैं। वनस्पति और जीव-जंतु ही धरती पर बेहतर और जरूरी पारिस्थितिकी मित्र प्रदान करते हैं। वन्य जीव चूंकि हमारे मित्र भी हैं, इसलिए उनका संरक्षण किया जाना बेहद जरूरी है।अब तक के शोधों से यह सामने आ चुका है कि धरती का पारिस्थितिकी तंत्र बेहद खराब हो चुका है। मानवीय दखल से दूर रहने के कारण और स्थानीय जनजातीय लोगों की भूमिका की वजह से सिर्फ तीन फीसद हिस्सा ही पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित रह गया है। ब्रिटेन स्थित स्मिथसोनियन एनवायरनमेंटल रिसर्च सेंटर के मुताबिक विश्व के केवल 2.7 फीसद हिस्से में ही अप्रभावित जैव विविधता बची है, जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी पांच सौ वर्ष पूर्व हुआ करती थी। इन क्षेत्रों में सदियों पहले जो पेड़-पौधे और जीव पाए जाते थे, वे प्रजातियां आज भी मौजूद हैं। जो अप्रभावित जैव विविधता वाला क्षेत्र बचा है, वह भी जिन-जिन देशों की सीमाओं के अंतर्गत आता है, उनमें से केवल ग्यारह फीसद क्षेत्र को ही संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है।

अप्रभावित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से अधिकांश इलाके उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, जहां मानव उपस्थिति कम रही है, लेकिन अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ये जैव विविधता से समृद्ध नहीं थे। धरती पर जैव विविधता के अस्तित्व पर मंडराते संकट को लेकर शोधकर्ताओं का कहना है कि अधिकांश प्रजातियां मानव शिकार के कारण लुप्त हुई हैं, जबकि कुछ अन्य कारणों में दूसरे जानवरों का हमला और बीमारियां शामिल हैं। हालांकि उपग्रह से मिली तस्वीरों के आधार पर शोधकर्ताओं का मानना है कि धरती के ऐसे बीस फीसद हिस्से की जैव विविधता को बचाया जा सकता है जहां अभी पांच या उससे कम बड़े जानवर ही गायब हुए हैं। लेकिन इसके लिए मानव प्रभाव से अछूते क्षेत्रों में कुछ प्रजातियों की बसावट बढ़ानी होगी, ताकि पारिस्थितिकीय तंत्र में असंतुलन पैदा न हो।

जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही गर्मी से भी जैव विविधता खतरे में पड़ी है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी आफ एरिजोना के शोधकर्ताओं का मानना है कि अगले पचास वर्षों में वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की प्रत्येक तीन में से एक यानी एक तिहाई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। शोधकर्ताओं ने दुनियाभर के छह सौ स्थानों पर पांच सौ से ज्यादा प्रजातियों पर एक दशक तक अध्ययन करने के बाद पाया कि अधिकांश स्थानों पर चौवालीस फीसद प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इस अध्ययन में विभिन्न मौसमी कारकों का अध्ययन करने के बाद शोधकर्ताओं इस नतीजे पर पहुंचे कि यदि गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो 2070 तक दुनियाभर में कई प्रजातियां खत्म हो जाएंगी।

वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वन्यजीवों की तस्करी भी दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़ा खतरा बन कर उभरी है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक तस्करी स्तनधारी जीवों की होती है। वन्यजीव तस्करी में बाईस फीसद तस्करी के मामले रेंगने वाले जीवों के और दस फीसद पक्षियों के होते हैं। जबकि पेड़-पौधों की तस्करी का हिस्सा 14.3 फीसद है।

इंटरनेशनल यूनियन फार कंजर्वेशन आफ नेचर (आइयूसीएन)की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में वन्यजीवों और वनस्पतियों की हजारों प्रजातियां संकट में हैं और आने वाले वक्त में इनके विलुप्त होने की संख्या और दर अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। आइयूसीएन ने करीब एक लाख पैंतीस हजार प्रजातियों का आकलन करने के बाद इनमें से सैंतीस हजार चार सौ प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर मानते हुए खतरे की सूची में शामिल किया है। करीब नौ सौ जैव प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और सैंतीस हजार से ज्यादा प्रजातियों पर विलुप्त होने का संकट मंडरा रहा है। यदि जैव विविधता पर संकट इसी प्रकार मंडराता रहा तो धरती पर से प्राणी जगत का खात्मा होने में सैकड़ों साल नहीं लगने वाले।

दुनिया के सबसे वजनदार पक्षी के रूप में जाने जाते रहे एलिफेंट बर्ड का अस्तित्व खत्म हो चुका है। इसी प्रकार एशिया तथा यूरोप में मिलने वाले रोएंदार गैंडे की प्रजाति भी अब इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन चुकी है। द्वीपीय देशों में पाए जाने वाले डोडो पक्षी का अस्तित्व मिटने के बाद अब कुछ खास प्रजाति के पौधों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है।

पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका के भारी बारिश वाले जंगलों में रहने वाले जंगली अफ्रीकी हाथी, अफ्रीकी जंगलों में रहने वाले काले गैंडे, पूर्वी रूस के जंगलों में पाए जाने वाले तेंदुए, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पाए जाने वाला बाघ जैसा विशाल जानवर भी अब अस्तित्व के खतरे से जूझ रहा है। हाल में 'स्टेट ऑफ वर्ल्ड बर्ड्स' नामक रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि दुनिया में पक्षियों की करीब उनतालीस फीसद प्रजातियों की संख्या स्थायी है और मात्र छह फीसद प्रजातियां ही ऐसी हैं, जिनकी संख्या बढ़ रही है, जबकि अड़तालीस फीसद प्रजातियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।

पक्षियों की प्रजातियों की संख्या में गिरावट को भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जहां चौदह फीसद प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं केवल छह फीसद प्रजातियों की संख्या ही स्थिर है, जबकि अस्सी फीसद प्रजातियां कम हुई हैं। इनमें से पचास फीसद प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट और तीस फीसद प्रजातियों में कम गिरावट दर्ज की गई है।

सालाना पक्षी गणना में अब प्रतिवर्ष पक्षियों की संख्या और विविधता में गिरावट आ रही है, जिसका बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और जंगलों का कटना है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पक्षियों पर हुए शोध के नतीजे भी चौंकाने वाले हैं। वहां वन क्षेत्रों में मानवीय दखल, वनों की कटाई और तेजी से बढ़ते प्रदूषण के कारण पक्षियों की संख्या में साठ से अस्सी फीसद तक की कमी आई है। देहरादून स्थित सेंटर फार इकोलाजी, डवलपमेंट एंड रिसर्च (सेडार) और हैदराबाद स्थित सेंटर फार सेल्युलर एंड मालिक्यूलर बायोलाजी (सीसीएमबी) के शोधकर्ता यह साझा शोध वर्ष 2016 से हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में कर रहे हैं।

बहरहाल, पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस प्रकार जंगलों में अतिक्रमण, कटाई, बढ़ता प्रदूषण और पर्यटन के नाम पर गैर जरूरी गतिविधियों के कारण पूरी दुनिया में जैव विविधता पर संकट मंडरा रहा है, वह पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का साफ संकेत है। यदि इसमें सुधार के लिए शीघ्र ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में बड़े नुकसान के तौर पर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।

विकास के नाम पर यदि वनों की कटाई जारी रही और जीव-जंतुओं और पक्षियों से उनके आवास छीने जाते रहे तो ये प्रजातियां धरती से एक-एक कर लुप्त होती जाएंगी और भविष्य में इससे पैदा होने वाली भयावह समस्याओं और खतरों का सामना समस्त मानव जाति को ही करना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैव विविधता के क्षरण का सीधा असर भविष्य में कृषि और खाद्य पैदावार इत्यादि पर पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी पर जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम पर्यावरणीय संतुलन को बिगड़ने न दें।

मिट्टी इतनी खराब कि सुधारने में लग जाएंगे तीस साल

(जग्गी वासुदेव, प्रसिद्ध धर्मगुरु)

मिट्टी का खराब होना एक वैश्विक घटना है। दुनिया की आधी ऊपरी मिट्टी नष्ट हो चुकी है। एक सामान्य कृषि-भूमि में न्यूनतम जैविक तत्व 3-6 प्रतिशत होने चाहिए, लेकिन दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में यह एक प्रतिशत से भी बहुत नीचे है। उत्तरी यूरोप में औसत जैविक तत्व 1.48 प्रतिशत है, दक्षिण यूरोप में 1.2 प्रतिशत, अमेरिका में 1.3 प्रतिशत, भारत में 0.68 प्रतिशत और अफ्रीका में 0.3 प्रतिशत है। इसका यह मतलब है कि धरती पर ज्यादतर कृषि-भूमि मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ रही है। जब बात जैवविविधता और मिट्टी की आती है, तो राष्ट्रीय सीमाओं के कोई मायने नहीं होते हैं। इसे वैश्विक स्तर पर संभालना होगा। अगर इस धरती पर जीवन के प्रति हमारी कोई प्रतिबद्धता है, अगर इस धरती पर भावी पीढ़ियों के लिए हमारी कोई प्रतिबद्धता है, तो हर देश के लिए यह करना जरूरी है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हर देश की नीतियों में मिट्टी और पर्यावरण के पुनरोद्धार को सम्मान देना।

अभी 'जागरूक धरती-मिट्टी बचाओ अभियान' का लक्ष्य एक वैश्विक नीति लाना है कि कृषि-भूमि में कम से कम 3-6 प्रतिशत जैविक तत्व होने चाहिए। हर कोई जानता है कि ऐसा होने की जरूरत है, पर समस्या यह है कि लोगों ने आवाज नहीं उठाई है। फिलहाल, दुनिया में 5.26 अरब लोग लोकतांत्रिक देशों में रहते हैं, यानी उन्हें वोट देने और अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। लोकतंत्र का अर्थ है, लोगों का शासन, पर अभी लोगों ने अपने जीवन के दीर्घकालीन हितों को अभिव्यक्त नहीं किया है।

मिट्टी को पुनर्जीवित करना 15-20 साल की एक प्रक्रिया है, तो ज्यादातर नेताओं की इसमें रुचि नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल सिर्फ 4-5 साल का होता है। अगर लोग ही सरकार से नहीं कहेंगे, तो सरकारें दीर्घकालिक निवेश कैसे करेंगी? इसी कारण मिट्टी बचाओ अभियान दुनिया भर में कम से कम 3.5 अरब लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ताकि सारे राजनीतिक दलों और सरकारों पर दीर्घकालिक मिट्टी पुनरोद्धार नीतियां बनाने के लिए जोर डाला जा सके।

अभियान के एक हिस्से के रूप में मैं लंदन से दक्षिण भारत तक 30,000 किलोमीटर की 100 दिनी यात्रा पर मोटरसाइकिल से अकेले कर रहा हूं। रास्ते में अनेक राष्ट्राध्यक्षों, कृषि एवं पर्यावरण मंत्रियों, प्रभावशाली लोगों और प्रसिद्ध हस्तियों से मुलाकात करता चलूंगा। हमने एक आम नीति दस्तावेज भी तैयार किया है। हमने दुनिया में 730 राजनीतिक दलों से कहा है कि आप अपने घोषणापत्र में मिट्टी पुनरोद्धार विषय को शामिल करें।

मिट्टी के लिए लोगों को आगे आना होगा। लोकतंत्र में लोगों की आवाज सबसे महत्वपूर्ण होती है। जरूरी नहीं कि हर कोई मिट्टी के संरक्षण में जुट जाए, हर किसी को केवल अपनी आवाज बुलंद करनी है।

अपनी सरकारों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम या आपके पास जो भी उपकरण हो। उस पर हर दिन 5-10 मिनट लगाइए और मिट्टी के बारे में कुछ कहिए। अगर हम 3.5 अरब लोगों को भी इन 100 दिनों के दौरान मिट्टी के बारे में बोलने के लिए प्रेरित कर सकें, तो धरती की कोई सरकार अनदेखी नहीं कर सकेगी।

मिट्टी के लिए लोग जागने लगे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि हमने आसानी से 1.3 अरब लोगों से संपर्क कर लिया है। सात से ज्यादा देश इस अभियान के साथ जुड़ गए हैं और अनेक देशों के साथ बातचीत जारी है। समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। राष्ट्रमंडल के 54 देशों ने अभियान में साथ देने का आश्वासन दिया है। संयुक्त राष्ट्र की अनेक संस्थाएं हमारे साथ भागीदारी कर रही हैं। मरुस्थलीकरण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सभा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर जैसी संस्थाएं सक्रिय हो गई हैं। अनेक संस्थाएं मिट्टी बचाओ अभियान के साथ अब मजबूत भागीदार हैं। हमें बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए कि हमें सफलता मिलेगी। जागने के साथ ही जल्दी पहल करने की जरूरत है। अगर हम अभी ठोस पहल करते हैं, तो अगले 25-30 साल में हम मिट्टी में काफी सुधार ला सकते हैं। ध्यान रहे, अगर हम पहल 50 साल बाद करते हैं, तो फिर मिट्टी को ठीक करने में 100-150 साल लग जाएंगे। इसका मतलब है कि चार या पांच पीढ़ियां मिट्टी की कमजोर स्थिति के चलते भयंकर जीवन स्थितियों से गुजरेंगी। कुछ लोगों के प्रयास से हमें सफलता नहीं मिलेगी। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि मिट्टी की ताकत लौटाने के लिए हम इस अभियान को बड़ा बनाएं, ताकि पृथ्वी प्राकृतिक रूप से ज्यादा सशक्त हो।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लापरवाही की लपटें

(मंगल सिंह)

दिल्ली के मुंडका में बहुमंजिली इमारत में लगी आग ने उपहार सिनेमा कांड की याद दिला दी। इतने वर्षों के बाद भी अगर दिल्ली सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना नामुमकिन होगा। केवल दिल्ली नहीं, हर महानगर में अग्निकांड की घटना सामान्य बात हो गई है। सवाल है कि आखिर आग की घटनाएं होती कैसे हैं और इनको रोका कैसे जाए। कहते हैं कि आग एक अच्छी दोस्त है, मगर बहुत बुरी मालिक। कितनी चिंता की बात है कि आगजनी की घटनाओं में भारत का एक तिहाई स्थान है।

अफसोस कि इन घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जिम्मेदार अधिकारियों का अपनी उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़ना। बहुमंजिली इमारतें बना दी जाती हैं, पर उनका सुरक्षा मानकों से कोई वास्ता नहीं होता है। कई इमारतें तो ऐसे हैं जो नगर निगम से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए वर्षों से संचालित हैं।कई बार ऐसा भी होता है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र किसी और व्यवस्था के लिए लेते हैं और संचालन किसी और का करते हैं। ऐसे में जिम्मेदार अभिकरणों को यह भी चाहिए कि वह समय-समय पर उसका निरीक्षण करें। इमारतों में जनसंख्या के हिसाब से आपातकालीन द्वार होने चाहिए। वेंटीलेशन की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। ओवरलोडिंग और शार्टशर्किट की घटनाएं कम से कम हों, यह सुनिश्चित करना चाहिए।आज शहरी मकान कंक्रीट के जंगल बने हुए हैं, महानगरों में इमारतों की इतनी सघनता है कि आग लगने की हालत में बच के निकलना मुश्किल होता है। शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका में वृद्धि करनी होगी, महानगर योजना समिति और जिला नियोजन समिति को नगर नियोजन के लिए वैश्विक मानक तय करना चाहिए। आग की घटनाओं को रोकने के लिए सबसे जरूरी है सजगता और सतर्कता। हमें आग लगने की पुरानी घटनाओं से सीखना होगा।

जनभागीदारी से प्रदेश की सीरत और सूरत बदलने में जुटे शिवराज

कृष्ण कान्त शुक्ल
युवा पत्रकार एवं शोधार्थी

मध्यप्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में लगातार 15 वर्षों से सत्ता में बनें रहना वाकई मुश्किल काम है, लेकिन जब जिद् और जज्बा एक साथ हो। फिर यह काम आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ करके इतिहास रच रहें हैं सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हो रहें समावेशी विकास की ही देन है कि कई बार उनके शासन को शिव %का% राज के रूप में देखा जाता है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ- सबका विकास की नीति वाली सरकार भले साल 2014 में बनी, लेकिन एमपी में शिव के विकास की गंगा काफ़ी पहले से अनवरत प्रवाहित हो रही है। देखा जाए तो जिस वक्त शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार सूबे की कमान अपने हाथ में ली थी। उस समय प्रदेश की आर्थिक हालत मलिन थी। प्रदेश अंधकार में डूबा था, लेकिन सूबे की सूरत और सीरत बदलने का जो जज्बा लेकर शिवराज सिंह चौहान सत्ता में काबिज़ हुए। उस मिशन में आज उनकी सरकार काफ़ी आगे निकल चुकी है और प्रदेश का स्वर्णिम इतिहास, भविष्य काल के लिए लिखा जा रहा है। आज प्रदेश हर मामले में उन्नति के पथ पर अग्रसर है। फिर भले ही विपक्ष अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए चोचलेबाजी करती रहें।

सूबे की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते 15 साल से जुटे हुए हैं और उनके आत्मसमर्पण और लगन का ही नतीजा है कि उन्हें अब प्रदेश में %मामा% की उपाधि भी दी जा चुकी है। वर्तमान भारतीय राजनीति में जनहितैषी नुमाओं की बेहद कमी प्रतीत होती है। उस दौर में शिवराज सिंह चौहान दिन-रात बे के वर्तमान को बेहतर करने में लगें हुए है। वैसे सूबे में शिवराज चौहान ही ऐसे ा हैं। जिनकी तारीफ़ में कसीदे विपक्षी नेता भी कई बार पढ़ते हैं और उनके ाज उत्थान के कामों की सराहना भी करते हैं। इतना ही नहीं %पांव पांव भैया% हे जाने वाले आज प्रदेश के ढाई करोड़ युवाओं के मामा है और उनका प्रदेश के ाओं से ये रिश्ता यूं ही नहीं बना। इसके पीछे 45 साल की कड़ी मेहनत और के अथक परिश्रम का परिणाम है। शिवराज सिर्फ आज के मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि प्रदेश के जन जन में एक अमिट छाप छोड़ने वाले प्रदेश के मुखिया है। शिवराज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री न भी रहे तो भी वो अपने मुखिया होने का फर्ज प्रदेश के युवाओं के लिए, माताओं बहनों और बुजुर्गों के लिए पूरा करते रहेंगे। उनमें समाज और समाज मे उनके प्रति कुछ कर गुजरने की ललक है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वे हमेशा प्रदेश के साथ खड़े रहे हैं।

प्रदेश में चाहे लाडली लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन हो या फिर संबल योजना। इसके अलावा कन्या विवाह या कोविड जैसे विषम हालात हो। वे कभी हार नहीं माने। ऐसे में यह कहें कि शिवराज सिंह चौहान सूबे के लिए एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश में ही रचबस गए हैं। तो यह कतई अतिश्योक्ति नहीं होगी। आने वाले दिनों में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हैं। ऐसे में देखें तो शिवराज सिंह चौहान ने परीक्षा चाहे छोटी हो या बड़ी हर चुनाव में पूरी ताकत लगाई है और भाजपा को मध्यप्रदेश के लिए सत्ता का पर्याय बना दिया है और यही वजह है कि शिवराज जी लंबे अरसे से मध्यप्रदेश में जन और जनता के दिलो में अपनी जगह बनाये हुए है। इनके नेतृत्व में गांव- शहर सभी विकास के रथ पर सवार हैं और सूबा जनभागीदारी के माध्यम से नित-नए कीर्तिमान लिख रहा है। गांवों का गौरव दिवस मनाने की मुहिम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की और पीएम नरेंद्र मोदी ने मुक्तकंठ से इस अभियान की सराहना की। प्रदेश के हर गांव का दिवस मनाया जाएगा, इससे आपसी सामाजिक समरसता का विकास होगा। इतना ही नहीं गांवों का कायाकल्प करना और जो गांव विकास की यात्रा में आज भी पीछे छूट गए हैं। उन्हें अग्रिम पंक्ति में लाना इस दिवस की थीम है।

गौरतलब हो कि शिवराज सिंह चौहान कोई भी काम अकेले नहीं करते। उनको पता है कि कोई भी अभियान हो। उसमें समाज की भागीदारी नहीं होगी तो उसके शत-प्रतिशत सफ़ल होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से गांवों को गोद लेने का अभियान चला। जिसके अच्छे परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं और अब उसी कड़ी में शिवराज जी ने %एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी% अभियान की शुरुआत की है। उनका मानना है कि जब तक सरकार का प्रयास और लोगों का जन समर्थन नहीं मिलेगा तब तक बदलाव नहीं हो सकता। इसीलिए अपने पूर्व अनुभवों से शिवराज सिंह ने आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को किसी भी चीज की कमी न हो। बच्चों के खाने, खेलने, पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। इसके लिए समाज को जोड़कर इस दिशा में प्रयास करने को सूबे की सरकार तत्पर है। ताकि लोगों में अपनत्व का भाव विकसित हो और आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ बच्चों का विकास हो। वैसे भी बच्चें किसी भी समाज, देश-प्रदेश के भविष्य होते हैं और उनके ही कंधें पर समाज का निर्माण आश्रित होता है। ऐसे में सरकार के इस कदम का हर स्तर पर स्वागत होना चाहिए और स्वस्थ भविष्य के निर्माण के लिए बच्चों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना होगा और यह तभी संभव है। जब आंगनवाड़ी जैसे संस्थान बेहतर हो।

मध्यप्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में लगातार 15 वर्षों से सत्ता में बनें रहना वाकई में मुश्किल काम है, लेकिन जब जिद् और जज्बा एक साथ हो। फिर यह काम आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ करके इतिहास रच रहें हैं सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हो रहें समावेशी विकास की ही देन है कि कई बार उनके शासन को शिव %का% राज के रूप में देखा जाता है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ- सबका विकास की नीति वाली सरकार भले साल 2014 में बनी, लेकिन एमपी में शिव के विकास की गंगा काफ़ी पहले से अनवरत प्रवाहित हो रही है। देखा जाए तो जिस वक्त शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार सूबे की कमान अपने हाथ में ली थी। उस समय प्रदेश की आर्थिक हालत मलिन थी। प्रदेश अंधकार में डूबा था, लेकिन सूबे की सूरत और सीरत बदलने का जो जज्बा लेकर शिवराज सिंह चौहान सत्ता में काबिज़ हुए। उस मिशन में आज उनकी सरकार काफ़ी आगे निकल चुकी है और प्रदेश का स्वर्णिम इतिहास, भविष्य काल के लिए लिखा जा रहा है। आज प्रदेश हर मामले में उन्नति के पथ पर अग्रसर है। फिर भले ही विपक्ष अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए चोचलेबाजी करती रहें।

सूबे की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते 15 साल से जुटे हुए हैं और उनके आत्मसमर्पण और लगन का ही नतीजा है कि उन्हें अब प्रदेश में %मामा% की उपाधि भी दी जा चुकी है। वर्तमान भारतीय राजनीति में जनहितैषी

शिवराज जी लंबे अरसे से मध्यप्रदेश में जन और जनता के दिलो में अपनी जगह बनाये हुए है। इनके नेतृत्व में गांव- शहर सभी विकास के रथ पर सवार हैं और सूबा जनभागीदारी के माध्यम से नित-नए कीर्तिमान लिख रहा है। गांवों का गौरव दिवस मनाने की मुहिम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की और पीएम नरेंद्र मोदी ने मुक्तकंठ से इस अभियान की सराहना की। प्रदेश के हर गांव का दिवस मनाया जाएगा, इससे आपसी सामाजिक समरसता का विकास होगा। इतना ही नहीं गांवों का कायाकल्प करना और जो गांव विकास की यात्रा में आज भी पीछे छूट गए हैं। उन्हें अग्रिम पंक्ति में लाना इस दिवस की थीम है।

साढ़े पाँच करोड़ वर्ष पहले भी था खरगोश!

आज हम जिस सुंदर-से खरगोश को देखते हैं, वह हमेशा से वैसा ही नहीं था। विकासवाद की धारा में बहते हुए उसने वर्तमान स्वरूप पाया है, लेकिन वह धरती पर करोड़ों वर्षों से रहता आया है। करोड़ों वर्ष पहले खरगोश कैसा था, इसका पता मंगोलिया में पाए गए साढ़े पाँच करोड़ साल पुराने खरगोश जैसे प्राणी के जीवाश्म से चलता है। गोम्फोस एल्केमा प्रजाति का यह प्राणी अब तक पाए गए खरगोश प्रजाति का सबसे पुराना सदस्य है।

आश्चर्य की बात तो यह है कि यह आधुनिक खरगोश से हूबहू मेल खाता है और बहुत संभव है कि यह अपने लंबे-लंबे पिछले पैरों से फुदकता था। इस जीवाश्म से इस विचार को बल मिलता है कि खरगोश जैसे प्राणी का विकास साढ़े छः करोड़ वर्ष पहले हुआ था। मंगोलिया में गोम्फोस का जो जीवाश्म पाया गया है, वह पूरी तरह से विकसित है, जिससे खरगोशों के पूर्वजों के शरीर की रचना की खासी जानकारी मिलती है। यह ढाँचा हमें बताता है कि आदिमकालीन खरगोश कैसे हुआ करते थे। इसके पैर किसी सच्चे खरगोश की तरह थे यानि कि पैर का आकार हाथ के आकार से लगभग दोगुना था। इसी के सहारे ये उछलकूद किया करते थे। आज के खरगोश और इनमें सिर्फ इतना फर्क था कि इनकी पूँछ ज्यादा लंबी थी और दाँत गिलहरी की तरह नुकीले थे। इस खोज से पूर्व जो सर्वाधिक परिपूर्ण जीवाश्म पाया गया था वह लेगोमार्फस अर्थात उस प्रजाति का था, जिसमें खरगोश, खरहा और रंगदुनी शामिल हैं। प्राणी शास्त्रियों का एक समूह मानता है कि आधुनिक प्लेसेंटल स्तनधारी का विकास सबसे पहले हुआ था जिनमें हाथी, चमगादड़, खरगोश तथा शेर तो शामिल हैं, लेकिन कंगारू, आपोसम या एकीडेंस शामिल नहीं थे। यह डायनासोर की समाप्ति के बाद कोई 65 करोड़ वर्ष पहले दुनिया में आए थे जबकि दूसरे समूह का मानना है कि आधुनिक प्लेसेंटल्स इस घटना के ठीक बाद अस्तित्व में नहीं आए थे। इस बात को लेकर वैज्ञानिकों के बीच घमासान जारी है कि गोम्फोस फुदकते थे या पैदल चलते थे। गोम्फोस का विश्लेषण बताता है कि आधुनिक लेगोमार्फस और अन्य प्लेसेंटल स्तनधारी डायनासोर की समाप्ति के बाद ही अस्तित्व में आए थे।

लंदन का टॉवर ब्रिज

लंदन का टॉवर ब्रिज जिसे लोग गलती से लंदन ब्रिज भी कहते हैं यह थेम्स नदी पर लंदन, इंग्लैंड में है। असल में लंदन टॉवर के समीप स्थित होने के कारण इसे टॉवर ब्रिज कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह बेसकूल ब्रिज है। बेसकूल ब्रिज का अर्थ है कि ऐसा ब्रिज जो जहाज के निकलने के लिए खुल जाता है और फिर से जुड़ सकता है। ऐसे पुल गतिशील पुल कहे जाते हैं और इनके खुलने और बंद होने में भी कम ऊर्जा लगती है। पहले यह पुल पानी और भाप से संचालित होता था लेकिन अब बेसकूल प्रणाली तेल और विद्युत से संचालित की जाती है। बेसकूल ब्रिज और भी कई स्थानों पर है जैसे-

- सालमोन ब्रिज, सिएटल, अमेरिका
- यूनिवर्सिटी ब्रिज, सिएटल, अमेरिका
- पीगेसस ब्रिज, फ्रांस
- जॉनसन स्ट्रीट ब्रिज, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा
- ग्राफ्टन ब्रिज, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया
- पैलेस ब्रिज, सेंट पीट्सबर्ग, रशिया
- मॉरीसन ब्रिज, आरेगन, अमेरिका

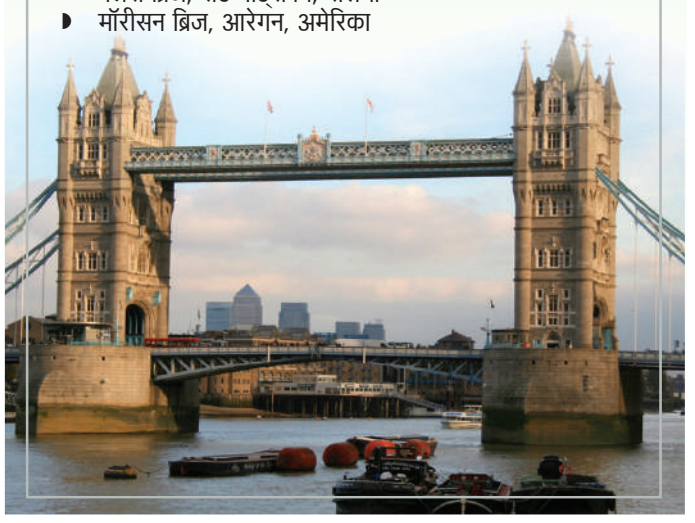

कीट केवल नुकसान ही नहीं करते, वे पर्यावरण के लिए अत्यंत जरुरी भी होते हैं। लेकिन आज दुनिया भर में कई कीटों की आबादी बड़ी तेजी से कम हो रही है

दुनिया भर में घट रहे हैं कीट

कीटों का अपना अलग ही संसार होता है। इनमें से कुछ हमारे आसपास तो कुछ दूर दराज के निर्जन स्थानों पर वास करते हैं। आमतौर पर हम अपने आसपास मधुमक्खी, मकड़ी, चींटी, मच्छर, तितली जैसे कीटों को रोज ही देखते हैं। इन कीड़ों ने भी इंसान के साथ रहने की आदत डाल ली है। पर ज्यादातर लोगों के मन में इनके प्रति ऐसी भावना बन गयी है कि कीट नुकसान पहुंचाते हैं। पर यह सही नहीं है। यह छोटे जीव हमारे लिए ही नहीं प्रकृति के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं।

हाल ही में जर्नल साइंस में छपे अध्ययन से पता चला है कि 1990 के बाद से कीटों की आबादी में करीब 25 फीसदी की गिरावट आ गई है। यह अध्ययन दुनिया भर की करीब 1676 स्थानों पर किये गए करीब 166 सर्वेक्षणों पर आधारित है। जिसमें साफ तौर पर पता चला है कि दुनिया भर में हर दस साल के अंदर करीब 9 फीसदी की दर से कीट कम हो रहे हैं। हालांकि दुनिया भर में जिस तरह नदियों और साफ जल स्रोतों को बचने की कवायद चल रहे है, उसके चलते मीठे पानी में रहने वाले कीटों में 11 फीसदी प्रति दशक की दर से वृद्धि देखी गई है।

कीटनाशक, बढ़ता शरीकरण और जलवायु परिवर्तन है कीटों के विनाश की मुख्य वजह शोधकर्ताओं के अनुसार दक्षिण एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बारे में कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, और जो है वो भी बहुत सीमित है। यही वजह है कि वहां पर कीटों में आ रही कमी का ठीक से आंकलन नहीं हो सका है। लेकिन इन क्षेत्रों में शहरीकरण तेजी से पैर पसार रहा है। साथ ही बड़े पैमाने पर खेती के लिए जंगलों और प्राकृतिक आवासों का विनाश हुआ है। कीट इंसानों के लिए भी बड़े जरुरी होते हैं यह फसलों और पेड़ पौधों को फैलने फूलने में सहायक होते हैं। साथ ही कई कीट तो प्रकृति में मौजूद वेस्ट को साफ भी करते हैं। इससे पहले जर्नल बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में छपे अध्ययन में भी कीटों के तेजी से घटने की बात को माना था। इस शोध में अनुमान लगाया गया था कि अगले कुछ दशकों में दुनिया के करीब 40 फीसदी कीट खत्म हो जायेंगे। जिनके लिए मुख्य रूप से सघन कृषि जिम्मेदार है। वहीँ भारी मात्रा में प्रयोग किये जा रहे कीटनाशक इन कीटों को तेजी से खत्म कर रहे हैं। इस अध्ययन में बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन को भी कीटों के विनाश की एक वजह माना था।

इस अध्ययन के प्रमुख और सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव बायोडायवर्सिटी रिसर्च जर्मनी में शोधकर्ता रोएल वॉन क्लिक ने बताया कि ''हालांकि इस शोध में कीटों के विनाश की जो दर आंकी गई है वो पहले के शोधों की तुलना में कम है। पर 24 फीसदी कुछ कम नहीं होता। जब मैं बच्चा था तब की तुलना में अब करीब एक चौथाई कीट कम हो गए हैं। लोगों को याद रखना चाहिए कि हम अपने भोजन के लिए इन्ही कीटों पर निर्भर हैं।''उनके अनुसार इस शोध में यह भी सामने आया है कि समय के साथ कीटों के विनाश की दर भी बदल रही है। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह रही कि यूरोप में कीट तेजी से खत्म हो रहे है। पश्चिमी और मध्य अमेरिका में भी इनमें तेजी से कमी आ रही हैम वही उत्तरी अमेरिका में धीरे-धीरे इनके विनाश की गति में कमी आ रही है। जबकि पूर्वी एशिया और अफ्रीका में जहां तेजी से शहरीकरण हो रहा है, और प्राकृतिक आवास कम हो रहे हैं। वहां इन कीटों का तेज गति से विनाश हो रहा है। अमेजन के जंगल तेजी से नष्ट हो रहें हैं जो ने केवल कीटों बल्कि वहां रहने वाले हर जीव के लिए खतरनाक है। हालांकि एक अच्छी बात यह रही की मीठे पानी के कीटों में 11 फीसदी प्रति दशक की दर से वृद्धि हो रही है पर इन कीटों की संख्या जमीनी कीटों की तुलना में कोई बहुत ज्यादा नहीं है।

यह धरती उसपर रहने वाले हर जीव की है। पर जिस तरह से मनुष्य अपनी अभिलाषा के लिए इसका दोहन कर रहा है उसके कारण अन्य जीवों पर भी असर पड़ रहा है। हमें समझना होगा कि धरती पर केवल हम अकेले नहीं है। हमें दूसरे जीवों का भी सम्मान करना होगा। आपसी निर्भरता प्रकृति के संतुलन का मूल है। यदि यह संतुलन बदला तो इसके विनाश का असर हर जीव पर पड़ेगा। ऐसे में मनुष्य भी उससे नहीं बचेगा। कीट भले ही बहुत छोटे होते हैं पर वो भी इस प्रकृति का हिस्सा हैं। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। दुनिया भर में एक महीने और उससे अधिक चले लॉकडाउन से जिस तरह पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ा है। वो इस बात का सबूत है कि यदि हम आज से पहल करें तो अब भी अपनी धरती को बचा सकते हैं। जिससे हमारा वजूद भी बचा रहे। वर्ना बाढ़, सूखा, तूफान और महामारियों के रूप में जो आपदाएं आ रही हैं वो समय के साथ और बढ़ती जाएंगी।

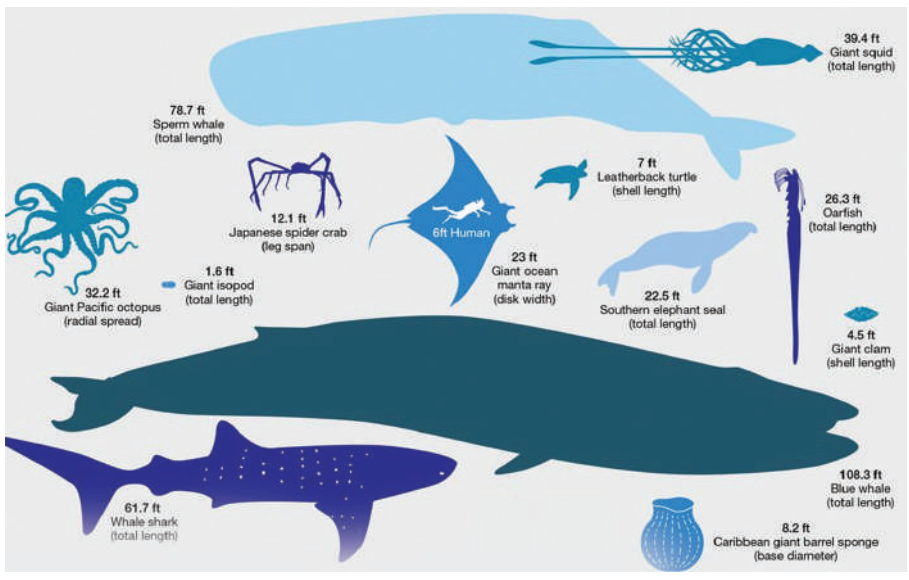

समुद्र के सबसे बड़े जानवरों को मेगापयूना कहते है। समुद्री मेगापयूना हमारे महासागरों के विशाल पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने भविष्य में इनके विलुप्त होने से, पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए समुद्री मेगापयूना प्रजातियों के लक्षणों की जांच की है।

खतरे में समुद्री मेगाफ्यूना

महासागरों में सबसे बड़े जानवरों के रूप में पाए जाने वाले, जिनके शरीर का द्रव्यमान 45 किलो से अधिक होता है, इसमें शार्क, व्हेल, सील और समुद्री कछुए शामिल हैं। ये प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्रों को संतुलित करने के लिए बड़ी मात्रा में बायोमास का उपभोग करते हैं। आवासों में पोषक तत्वों को ले जाती है तथा महासागरीय पारिस्थितिक तंत्रों को जोड़ती हैं। इनके पारिस्थितिक कार्य इनके लक्षणों से निर्धारित होते है, जैसे कि वे कितने बड़े हैं, वे क्या खाते हैं, और कितनी दूरी तय करते हैं आदि। इनके लक्षणों की विविधता को मापने से वैज्ञानिकों को पारिस्थितिक तंत्र के लिए समुद्री मेगाफ्यूना का योगदान कितना है, उसे निर्धारित करने और उनके विलुप्त होने की आशंका आदि के आकलन करने में मदद मिलती है।

यूके की स्वानसी विश्वविद्यालय के डॉ.कैटालिना पिमिएंटो के नेतृत्व में यह शोध कार्य किया गया है। जिसमें शोधकर्ताओं की टीम ने पहली बार समुद्री प्रणालियों में किए जाने वाले पारिस्थितिक कार्यों को समझने के लिए, सभी जानी-पहचानी समुद्री मेगाफ्यूना के प्रजाति-स्तरीय विशेषताओं का डेटासेट तैयार किया है। भविष्य में प्रजातियों के विलुप्त होने के परिदृश्यों, उनके कार्यों में विविधता, इनके नुकसान से पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने के बाद, शोधकर्ताओं ने इनके संरक्षण के लिए एक नया सूचकांक बनाया है। परिणामों में समुद्री मेगाफ्यूना द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विविध श्रृंखला को दिखाया गया है, साथ ही यह भी दिखाया कि उनके विलुप्त होने पर मौजूदा जैव विविधता किस तरह प्रभावित हो सकती है।

यदि इसी तरह चलता रहा, तो अगले 100 वर्षों में औसतन 18% समुद्री मेगाफ्यूना की प्रजातियों का नुकसान हो सकता है, जिससे पारिस्थितिक कार्यों में 11% का नुकसान होगा। फिर भी, यदि वर्तमान में सभी खतरे वाली प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, तो हमें 40% प्रजातियों और 48% पारिस्थितिक कार्यों का नुकसान सहना होगा। शार्क का सबसे अधिक प्रभावित होने का पूर्वानुमान लगाया गया है।

डॉ.कैटेलिना पिमिएंटो ने कहा हमारे नए अध्ययन से पता चलता है कि, आज मेगाफ्यूना की अनूठी और विविध पारिस्थितिक भूमिकाएं मानव दबावों के कारण गंभीर खतरे का सामना कर रही हैं। इन प्रजातियों के दुनिया भर से विलुप्त होने के संकट को देखते हुए, एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि प्रकृति किस हद तक इन्हें दुबारा जन्म देगी। विलुप्त होने की स्थिति में, क्या शेष प्रजातियां जीवित रहेंगी जो इनके समान पारिस्थितिक भूमिका निभा सकती हैं?

स्वानसी विश्वविद्यालय के अध्ययनकर्ता डॉ.जॉन ग्रिफिन कहते हैं कि हमारे परिणाम बताते हैं कि महासागरों के सबसे बड़े जानवरों की संख्या सीमित होती जा रही है। यदि प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, तो पारिस्थितिक कार्य नहीं होगें। यह एक चेतावनी है कि हमें जलवायु परिवर्तन सहित समुद्री मेगाफ्यूना पर बढ़ते मानव दबाव को कम करने के लिए अभी से कार्य करने की आवश्यकता है।

सीसीटीवी
इलेक्ट्रॉनिक चौकीदार

हाइस्ट्रीट, शॉपिंग सेंटर्स, पब्स, कार पार्किंग से लेकर जिंदगी के हर मुकाम तक ताँकझाँक करने के बाद अब क्लोज सर्किट टीवी ने घरों में अपनी दस्तक देना आरंभ कर दिया है। हालात यहां तक पहुँचे हैं कि आधुनिक घरों में डोर बेल और मेजिक आई की तरह सीसीटीवी भी जरूरी हो गए हैं

अब के.पॉवेल का घर ही लीजिए। बार-बार उसके घर का शीशा तोड़ दिया जाता था। अपने दरवाजे के सामने बिखेरे जाने वाले कचरे से भी वह बेहद परेशान थी। आखिरकार उसने 1000 पौंड खर्च कर तकनीकी विशेषज्ञ की मदद से ऐसी सीसीटीवी प्रणाली लगाई जिसका कैमरा न केवल प्रॉपर्टी पर निगरानी रखता था बल्कि सीधे हार्ड ड्राइव पर रिकॉर्डिंग भी करता था। उसकी मदद से उसने न केवल शरारती तत्वों को पकड़वा दिया बल्कि अच्छा-खासा मुआवजा भी वसूल किया। अभी तक लोग घर की सुरक्षा के लिए घरों में स्पाई कैमरा, बर्गलर अलार्म, आउटडोर लाइट्स और पेनिक बटनों का उपयोग करते आ रहे थे। लेकिन सीसीटीवी ने घटना को देखने के अलावा उसे रिकॉर्ड कर साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने की सुविधा भी प्रदान कर दी है। सीसीटीवी की घरों में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए घरेलू सामान बेचने वाले स्टोरों में परंपरागत सामानों के साथ सीसीटीवी प्रणालियों के बक्से भी सजे दिखाई देने लगे हैं। इनकी कीमतें 30 पौंड वाले ब्लैक एंड व्हाइट उपकरण से आरंभ होती हैं। अब अपने दरवाजों पर कैमरा लगाने के लिए किसी को सेलेब्रिटी, करोड़पति व्यापारी या नेता होने की आवश्यकता नहीं है

क्या हैं बीटा टेस्टर

किसी भी सॉफ्टवेयर के बनने के बाद उसमें खामियाँ या गलतियों को चेक करने की एक प्रक्रिया होती है। जो कंपनी या व्यक्ति सॉफ्टवेयर तैयार करता है वह पहले अपने स्तर पर खामियों को नोट करता है और उन्हें दूर करता है। इसे अल्फा टेस्टर कहते हैं। इसी तरह यह सॉफ्टवेअर बाजार में आने से पहले कुछ चुनिंदा यूजर्स के पास भी जाता है जिसे वे चेक करते हैं और गलतियों का पता लगाते हैं। इन्हें बीटा टेस्टर कहते हैं। चूँकि डेवलपर पहले गलतियों को तलाशता है और यूजर बाद में इसलिए क्रमानुसार इन्हें अल्फा और बीटा टेस्टर कहते हैं।

'सॉफ्ट बॉइल्ड एग' नियम क्या है?

कम्प्यूटर में विभिन्न कामों को करने के लिए जो सॉफ्टवेअर बनाए जाते हैं उन्हें अप्लीकेशन सॉफ्टवेअर कहते हैं। इसे सॉफ्टवेअर विशेषज्ञ तैयार करते हैं। इस तरह का सॉफ्टवेअर तैयार करते हुए विशेषज्ञों को ध्यान रखना होता है कि बनने वाला सॉफ्टवेअर यूजर के लिए आसान हो और उसकी उपयोगिता भी ज्यादा हो। इस नए सॉफ्टवेअर के कामकाज को समझने में यूजर को ज्यादा समय न लगे यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोटे तौर पर इस नए सॉफ्टवेअर की किसी विशेषता को समझने में या इसे ऑपरेट होने में तीन मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। इसे 'सॉफ्ट बॉइल्ड एग' नियम कहा जाता है। क्योंकि एक अंडे को भी उबलने में सामान्य तौर पर तीन मिनट लगते हैं।

अमेरिका के स्कूल में फायरिंग

18 साल के स्टूडेंट ने 19 बच्चों समेत 21 लोगों की जान ली

वाशिंगटन

अमेरिकी राज्य टेक्सास से मंगलवार दोपहर को दिल दहलाने वाली खबर आई। टेक्सास के युवाल्डे में रॉब एलिमेंट्री स्कूल में एक 18 वर्षीय युवक ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 19 स्टूडेंट और 2 टीचर की मौत हो गई। फायरिंग में 13 बच्चे, स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और कुछ पुलिसवाले भी घायल हुए हैं। हमलावर ने स्कूल में फायरिंग से पहले अपनी दादी को भी गोली मारी है। उन्हें एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया है। घटना के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर हमें पूछना चाहिए कि गन लॉबी के खिलाफ हम कब खड़े होंगे और वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। माता-पिता अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाएंगे। बहुत सारी आत्माएं आज कुचली गई हैं। यह वक्त है जब हमें इस दर्द को एक्शन में बदलना है। पुलिस अधिकारियों ने हमलावर को मारने

हमले से पहले रैमोस ने राइफल की तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी।

का दावा किया है। उसकी पहचान 18 साल के साल्वाडोर रैमोस के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावर खुद भी स्टूडेंट है। टेक्सास के स्कूल में फायरिंग की यह घटना कनेक्टिकट में 2012 में हुई फायरिंग से मिलती हुई है। कनेक्टिकट के न्यूटाउन में सैंडी हुक एलिमेंट्री हाईस्कूल में 14 दिसंबर 2012 को 20 वर्षीय युवक ने फायरिंग की थी। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, इनमें 20 बच्चे थे। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे भयावह मास शूटिंग थी।

सोशल मीडिया पर संदिग्ध की फोटो, पर आधिकारिक पुष्टि नहीं

टेक्सास गवर्नर एबॉट ने जब बताया कि हत्यारे की पहचान सल्वाडोर रामोस के तौर पर हुई है, तब सोशल मीडिया पर एक युवक की फोटो वायरल हो गई। यह इंस्टाग्राम पेज सल्वाडोर रामोस का बताया जा रहा है। इस पर एक युवक की मोबाइल के साथ फोटो है। इसके अलावा पेज पर राइफल की फोटोज भी पोस्ट की गई हैं। बताया जा रहा है कि यही टेक्सास फायरिंग का संदिग्ध है। हालांकि, अभी तक इन फोटोज की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यह इंस्टाग्राम पेज भी शूटिंग के कुछ ही देर बाद हटा दिया गया।

स्कूल की पेरेंट्स से अपील- अभी यहां न आएं

इधर, घटना के बाद स्कूल ने सभी पेरेंट्स से अपील की है कि वे अभी बच्चों को लेने न आएं। स्कूल की ओर से कहा गया है कि जब तक पुलिस की टीम पूरे इलाके को सुरक्षित नहीं कर लेती है, तब तक आप लोग न आएं। सभी बच्चों को स्कूल प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है।

दोषियों को बख्शेंगे नहीं:- टेक्सास के गवर्नर ने कहा कि हत्यारा 18 साल का है और उसने रायफल से फायरिंग की है। हालांकि, पुलिस के साथ एनकाउंटर में वो भी मारा गया है।

जम्मू-कश्मीर में एनकाउंटर

बारामूला में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, 24 घंटे में दो जवान भी शहीद

बारामूला

बारामूला के करेरी इलाके की नजीभात क्रॉसिंग पर सेना और आतंकियों के बीच बुधवार सुबह मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षाबलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुआ है। एनकाउंटर में जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। ङ्कत्रक्क कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि अभी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।

मंगलवार को भी एक पुलिसकर्मी की हत्या हुई थी

जम्मू-कश्मीर में आतंकी बीते कई दिनों से टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मंगलवार को आतंकियों ने श्रीनगर के सौरा क्षेत्र के अचार इलाके में पुलिसकर्मी पर हमला किया। आतंकियों ने पुलिसकर्मी को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात में उनकी 9 साल की बेटी सफा कादरी भी गोली लगने से जख्मी हो गई। सफा की ालत फिलहाल स्थिर है।

राहुल भट की हत्या के विरोध में कश्मीरी पंडितों ने सिर मुंडवाकर विरोध जताया।

राहुल भट की हत्या की विरोध में प्रदर्शन

12 मई को जम्मू-कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने चडूरा तहसीलदार ऑफिस के क्लर्क राहुल भट को ऑफिस में घुसकर गोली मार दी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 21 मई को अनंतनाग जिले के कश्मीरी पंडितों ने सिर मुंडवा कर राहुल भट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने राहुल भट की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। पंडितों ने जागो मोदी-जागो मोदी, शहीद राहुल भाई अमर रहे, राहुल तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे नारे लगाए। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षित माहौल क्यों नहीं बना रहा है? जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले में मारे गए राहुल भट के परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी।

पाकिस्तान में खूनखराबे का खतरा : इस्लामाबाद में धरने पर अड़े इमरान

इस्लामाबाद

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज इस्लामाबाद तक लंबा मार्च करके वहां बेमियादी धरने पर बैठने जा रहे हैं। इसके पहले देर रात पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। जियो न्यूज के मुताबिक, पुलिस ने क्क्रञ्जढ्ढ नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी की। इस दौरान नेता मियां महमूद-उर-रशीद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लंबी चुप्पी के बाद शाहबाज शरीफ सरकार ने भी खान को करारा जवाब दिया। होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने कहा- दम है तो इस्लामाबाद के रेड जोन में आकर देखें इमरान। जवाब में खान ने युवा समर्थकों को उकसाया। कहा- सरकार के हर हमले

का उसी अंदाज में जवाब दें। हालात बिगड़ते देख अब तक कथित तौर पर न्यूट्रल रहने वाली फौज भी एक्शन में आई। होम मिनिस्ट्री से बातचीत के बाद इस्लामाबाद के ज्यादातर हिस्सों में फौज और रेंजर तैनात कर दिए गए हैं।

पंजाब में सरकारी नौकरी के लिए पंजाबी अनिवार्य:पंजाबी योग्यता टेस्ट में 50 फीसदी अंक जरूरी; सीएम मान बोले- पंजाबियत सबसे पहले

पंजाब

पंजाब में सरकारी नौकरी के लिए पंजाबी अनिवार्य कर दी गई है। ष्टरू भगवंत मान ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए पंजाबी टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इसके टेस्ट में कम से कम 50 फीसदी अंक जरूरी होंगे। मान ने कहा कि मां बोली पंजाबी पूरी दुनिया में हमारी पहचान है। पंजाबी को हर पक्ष से प्रफुल्लित करना हमारी सरकार का मुख्य मकसद है।

ग्रुप सी और डी के लिए होगा लागू

पंजाब सरकार का यह आदेश ग्रुप सी और डी की सरकारी भर्ती में लागू होगा। ग्रुप

सी में क्लेरिकल स्टाफ आएगा। वहीं डी में चपरासी, सफाई कर्मचारी जैसे क्लास फोर कर्मचारी आएंगे। पंजाब सरकार के इस आदेश से इन पदों पर पंजाबी मूल या फिर स्कूलों में पंजाबी पढ़ने वालों को नौकरी के ज्यादा मौके मिलेंगे।

सरकार कर रही 26,754 की भर्ती

पंजाब की मान सरकार 26,754 पदों पर सरकारी भर्ती कर रही है। इस लिहाज से यह बड़ा फैसला है। इनमें से कई पदों की भर्तियां निकाली जा चुकी हैं। वहीं कई के विज्ञापन आने बाकी हैं। पंजाबियों के बजाय बाहरी लोगों को ही यह नौकरियां न मिलें, इसके लिए मान सरकार ने यह कदम उठाया है। इन पदों पर सबसे ज्यादा गिनती ग्रुप सी और डी कैटेगरी की ही है।

न्यूज ब्रीफ

पंजाब सरकार के हेल्थ मिनिस्टर गिरफ्तार

कुछ देर पहले सीएम मान ने बर्खास्त किया था, टेंडर और खरीद-फरोख्त में कमीशन का आरोप था

पंजाब। पंजाब में आम आदमी पार्टी (क्क) की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉ. विजय सिंगला को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है। विजय सिंगला स्वास्थ्य विभाग में हर काम और टेंडर के बदले 1त्न कमीशन मांग रहे थे। इसकी शिकायत सीएम भगवंत मान तक पहुंची थी। उन्होंने गुपचुप तरीके से इसकी जांच कराई। अफसरों से पूछताछ की, फिर मंत्री सिंगला को तलब किया गया। मंत्री ने गलती मान ली, इसके बाद उन्हें बर्खास्त किया गया। इसके बाद मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर पंजाब पुलिस के एंटी करप्शन विंग ने सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद अब सिंगला की आम आदमी पार्टी से भी छुट्?टी करने की तैयारी है। पंजाब आप के प्रवक्ता मालविंदर कंग ने कहा कि दागी लोगों की आम आदमी पार्टी में कोई जगह नहीं है। फिलहाल मंत्री रहे सिंगला की इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

सीएम मान ने बताई पूरी कहानी

सीएम भगवंत मान ने बताया, मेरे ध्यान में एक केस आया। इसमें मेरी सरकार का एक मंत्री हर टेंडर या उस विभाग की खरीद-फरोख्त में एक परसेंट कमीशन मांग रहा था। इस केस का सिर्फ मुझे पता है। इसके बारे में विरोधी पार्टियों और मीडिया को पता नहीं है। मैं चाहता तो केस को दबा सकता था, लेकिन इससे लोगों का विश्वास टूट जाता। मैं उस मंत्री के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा हूं। उसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस को उसके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आदेश दे दिए हैं।% अरविंद केजरीवाल ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे भगंवत मान पर गर्व है। उनकी कार्रवाई से मेरी आंखों में आंसू आ गए। पूरा देश आज आम आदमी पार्टी पर गर्व महसूस कर रहा है।

कांग्रेस के नेशनल प्लान में प्रियंका की एंट्री

2024 के लिए टास्क फोर्स बनाई, पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप में जी-21 गुट के दो नेताओं को जगह

नई दिल्ली

कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। साथ ही 8 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी भी बनाई है। कांग्रेस की पीएसी में सांसद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अम्बिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनन्द शर्मा, केसी वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। अगर 2024 चुनाव के लिए बनाए गए टास्क फोर्स के सदस्यों पर नजर डालें तो इसमें पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, सुनील कनगोलु का नाम है।

भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को मजबूत करना मकसद:- सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर भारत जोड़ो यात्रा में कई बड़ें चेहरों को शामिल किया गया है। इसमें दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, शशि थरूर, रंवीत सिंह बिट्टू, केजे जॉर्ज, जोथी मानी, प्रद्युत बोलदोलोई, जीतू पटवारी, सलीम अहमद को शामिल किया गया है। कांग्रेस ने हाल ही में पार्टी की स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए उदयपुर में चिंतन शिविर बुलाया था। इस शिविर में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगठनात्मक बदलाव की बात कही थी। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप और टास्क फोर्स के गठन का ऐलान भी किया था।

दावोस में जेलेंस्की की अपील, कहा-

रूस छोड़ने वाली कंपनियां यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट करें, जंग रोकने के लिए सिर्फ पुतिन से बात करुंगा

कीव

रूस-यूक्रेन का आज 90वां दिन है। दोनों देशों के बीच जंग अभी भी जारी है। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोमवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया के बड़े कंपनियों से गुजारिश कि की वे रूस से निकलकर यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट करें। जेलेंस्की ने कहा- मैं पुतिन के अलावा के रूस के किसी भी अधिकारी के साथ जंग रोकने के मसले पर बात नहीं करुंगा। इसके अलावा किसी दूसरे मुद्दे पर बातचीत का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि राजधानी कीव के उत्तर में चेर्निहीव इलाके में पिछले हफ्ते रूसी हमले में 89 लोग मारे गए। जेलेंस्की के मुताबिक, जंग के शुरुआती दिनों में ऐसा पहली बार है जब एक साथ इतने यूक्रेनी नागरिक मारे गए हों। जेलेंस्की ने कहा कि हम अपने देश को नए सिरे से तैयार करना चाहते हैं। हमारे देनसा शहर में रूस ने 89 नागरिकों का कत्ल किया है। जुलाई में लुगानो कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यहां हम सभी देशों से अपील करेंगे कि वो

यूक्रेन के कीव में मायखाइलिवस्का स्क्वायर में राष्ट्रीय सैन्य इतिहास संग्रहालय द्वारा नष्ट किए गए रूसी सैन्य वाहनों का प्रदर्शन।

यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट करें। जेलेंस्कि ने का कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो रूस छोड़ रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इकोनोमिक फोरम में शामिल होने पर जेलेंस्की को स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया।

स्टारबक्स रूसी बाजार से निकल रहा बाहर

दुनिया के सबसे बड़े कॉफी शॉप स्टारबक्स ने रूसी बाजार से बाहर निकलने की घोषणा की है। उसने अपने 130 स्टोर बंद करने का फैसला किया है। अब रूस में इस ब्रांड की उपस्थिति नहीं होगी। स्टारबक्स ने कहा कि वह अपने लगभग 2,000 रूसी कर्मचारियों को छह महीने तक भुगतान करना जारी रखेगा और उन्हें नई नौकरियों में बदलने में मदद करेगा। स्टारबक्स ने पिछले सप्ताह मैकडॉनल्ड्स के रूसी बाजार से बाहर निकलने के बाद यह कदम उठाया है। मैकडॉनल्ड्स अपनी दुकानें बेच रही है। स्टारबक्स ने 2007 में रूसी बाजार में प्रवेश किया था। कान्स में चल रहे 75वें फिल्म समारोह में रविवार को रेड कार्पेट इवेंट बाधित रहा। यहां यूक्रेन समर्थक महिला प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन में महिलाओं पर हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया।

PRESS ITDC
ITDC NEWS
www.itdcindia.com

मध्य भारत से विश्वसनीय हिन्दी दैनिक समाचारपत्र
आईटीडीसी न्यूज़,

विश्वसनीयता की अपेक्षा पर सच्चा बनाने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं,
प्रति सप्ताह आप सभी का स्तम्भ

मेरे लोग, मेरा विधान

इसके तहत हम आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि
विश्लेषणात्मक रचनाएं, जनसामान्य हित में
नई जानकारियां, लेख, आलेख, टीका, विवेचना, समाचार, रोचक तथ्य,
नए प्रयास, अभिनव प्रयोग के रूप में हमें प्रेषित करें।

आपकी रचना, नाम, चित्र सहित, अधिकाधिक पाठकों तक पहुंचे,
इसके लिए हम, समाचार पत्र में प्रकाशित रचनाओं को,
देश के सभी प्रचलित सोशल मीडिया स्टैंड जैसे फेसबुक, लिंकेडीन, यूट्यूब, जीटॉक, टिवीटर, इंस्टाग्राम
व्हाट्सएप्प एवं हमारे डिजिटल स्टैंड से प्रचार-प्रसार भी देंगे।
(दीर्घ समय तक https://www.itdcindia.com/saga-news.php पर भी उपलब्ध)
जिससे लाभान्वित जनों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे।

आप सभी इच्छुकजन अपनी गैरमानदेय,
अपठित, नवीन, मूल एवं मौलिक रचना, हिन्दी में हमें प्रेषित करें।
(और अंग्रेजी में भेजने पर केवल हमारे डिजिटल स्टैंड पर ही प्रकाशन होगा)
उक्त हेतु, आपका चित्र, नाम, शहर, मोबाइल न, आपकी रचना, मेल करें-ईमेल
itdcnewsmp@gmail.com

मध्य भारत का विश्वसनीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
इंटीग्रेटेड ट्रेड डेव्हेलपमेंट सेंटर न्यूज़

क्या वाइड के लिए भी रिव्यू का विकल्प होना चाहिए ?

नई दिल्ली

आईसीसी एलीट पैनल के पूर्व अंपायर साइमन टॉफ़ल नहीं चाहते हैं कि टी20 क्रिकेट में वाइड और हाइट नो-बॉल में टीमों के पास रिव्यू लेने का विकल्प हो। टॉफ़ल की राय भारत और राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युज़वेंद्र चहल से विपरीत है, जो मानते हैं कि गेंदबाज़ों को थोड़ी और मदद की ज़रूरत है। चहल का मानना है कि वाइड और हाइट नो बॉल को रिव्यू कर के टीमें एक मौक़ा ले सकती हैं जो संभावित रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ईएसपीएनक्रिकइंफ़ो के साथ बात करते हुए चहल ने कहा कि 10 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के विरुद्ध लीग मैच के दौरान उन्हें संभावित रूप से अंपायर की एक ग़लत कॉल का सामना करना पड़ा था। अपने चौथे ओवर की चौथी गेंद पर चहल ने एक लेग ब्रेक गेंद फेंकी जो दुश्मांता चमीरा के ऑफ़ स्टंप के बाहर पिच हुई और फिर बाहर निकली। अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया। चहल इस फ़ैसले से असहमत थे और उन्होंने अंपायर से इस बारे में बात भी की थी। चहल ने अगली गेंद पर श्रीलंकाई बल्लेबाज़ को पगबाधा आउट कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक अतिरिक्त गेंद उन्हें महंगी पड़ी क्योंकि मार्कस स्टॉयनिस ने उनके स्पेल की अंतिम गेंद पर छक्का लगाया। अंपायर की इस कॉल से मैच का परिणाम लगभग प्रभावित हो गया था, हालांकि राजस्थान उस मैच को तीन रनों से जीत गई। चहल से पूछा गया कि क्या वाइड के लिए भी रिव्यू विकल्प को भी टीमों को मिलने वाले दो रिव्यू में शामिल करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, अंपायर भी इंसान हैं। वे ग़लती कर सकते हैं, लेकिन दो टीमों के बीच कई बार हार का अंतर एक रन का भी हो सकता है। लखनऊ के ख़िलाफ़ मेरे साथ ऐसा हुआ था जब अंपायर ने वाइड का इशारा किया था, लेकिन जब मैंने इसे रिप्ले पर देखा

तो यह वाइड नहीं था। इसके कारण मुझे एक अतिरिक्त गेंद फेंकनी पड़ी और मेरी आख़िरी गेंद पर छक्का भी लगा। यह सात गेंदों का ओवर बन गया और विपक्षी टीम सात अतिरिक्त रन बनाने में सफल रही। चूंकि टी20 बल्लेबाज़ों के वर्चस्व वाला खेल है, अगर गेंदबाज़ों को थोड़ी और मदद मिलती है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। कुछ हफ़्ते बाद राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन 2 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के ख़िलाफ़ मैच में नाराज़ हो गए, जब मैदानी अंपायर नितिन पंडित ने प्रसिद्ध कृष्णा द्वारा डाले गए 19वें ओवर के दौरान तीन मौक़ों पर वाइड का संकेत दिया। सैमसन ने नितिन की ओर इशारा किया कि कृष्णा के गेंद फेंकने से पहले ही बल्लेबाज़ क्रीज़ के अंदर शफ़ल कर रहा है तो यह वाइड कैसे है। इस मैच में कोलकाता विजयी रही थी।

मैच के बाद की घटना का विश्लेषण करते हुए, ईएसपीएनक्रिकइंफ़ो के विशेषज्ञ डेनियल वेटोरी और इमरान ताहिर ने सहमति व्यक्त की कि गेंदबाज़ों को दो रिव्यू के माध्यम से अंपायरिंग त्रुटियों को सुधारने का विकल्प होना चाहिए। इस सीज़न में आईपीएल ने एक अतिरिक्त रिव्यू टीमों को दिया है, चहल ने कहा कि यह पर्याप्त है और हम इससे ख़ुश हैं। इस सप्ताह के अंत में प्रकाशित होने वाले एक साक्षात्कार में टॉफ़ल ने ईएसपीएनक्रिकइंफ़ो को बताया, मैं निर्णय लेने की कला को विज्ञान में बदलने और सटीकता की तलाश करने को लेकर जो प्रयास हो रहे हैं, उससे सचेत हूं। उदाहरण के तौर पर वाइड को लिया जा सकता है। अगर आपके अनुसार या खिलाड़ी के अनुसार चलें और वाइड को यदि थर्ड अंपायर के पास रेफ़र किया जाता है तो ऐसा हो सकता है कि यह एक बहुत ही नज़दीकी फ़ैसला हो। इसके बाद अगर तीसरे अंपायर इस फ़ैसले में हस्तक्षेप करते हैं, तब भी उस फ़ैसले में तर्क की गुंजाइश रह जाएगी। टॉफ़ल ने कहा कि वाइड को लेकर फ़ैसला लेना कभी भी आसान काम नहीं रहा है। इसको लेकर कभी भी क्रिकेट के नियमावली और खेल की परिस्थितियों में एक निश्चित परिभाषा नहीं रही है। क्या आप थर्ड अंपायर के रूप में लेग स्टंप के बाहर की गेंद को वाइड करार दिए जाने के फ़ैसले को चिन्हित करने या उसे पहचानने में सफल हो सकते हैं? किसी वाइड गेंद को रिव्यू करने के लिए थर्ड अंपायर के जाना निश्चित रूप से एक दिलचस्प प्रस्ताव है।

न्यूज ब्रीफ

भारत एएफसी अंडर-17, अंडर-20 एशिया कप क्वालीफायर के ग्रुप डी और एच में

नई दिल्ली। भारत को एएफसी (एशियाई फुटबॉल परिसंघ) के अंडर-17 और अंडर-20 एशियाई कप फुटबॉल क्वालीफायर में क्रमशः ग्रुप डी और एच में जगह मिली है। ये क्वालीफायर इसी साल होने हैं। एएफसी अंडर-17 चैंपियनशिप क्वालीफायर में बिबियानो फर्नांडिस के मार्गदर्शन में खेलने वाली भारत की लड़कों की अंडर-17 टीम अक्टूबर में सऊदी अरब के दम्मान में मालदीव, कुवैत और म्यांमार से भिड़ेगी। इस बीच शानमुगम वेंकटेश के मार्गदर्शन में खेलने वाली भारत की अंडर-20 पुरुष टीम सितंबर में इराक के बसरा में मेजबान इराक, आस्ट्रेलिया और कुवैत से भिड़ेगी। दोनों ही टूर्नामेंट में ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाली टीम और दूसरे स्थान पर रहने वाली पांच सर्वश्रेष्ठ टीम 2023 में क्रमशः बहरीन और उज्बेकिस्तान में एएफसी अंडर-17 और एएफसी अंडर-20 एशियाई कप के लिए क्वालीफाई करेंगी।

विश्व चैंपियनशिप की हार से अहम सबक सीखा : लवलीना

नई दिल्ली। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों से पहले आईबीए विश्व चैम्पियनशिप के प्री-क्वार्टर फाइनल से बाहर होने को एक बहुत जरूरी 'सीख% मानती है। तोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना का विश्व चैम्पियनशिप में अभियान 70 किग्रा वर्ग के प्री-क्वार्टर फाइनल में निराशाजनक हार के बाद समाप्त हुआ था। पिछले साल तोक्यो में पोडियम पर अपना अभियान खत्म करने के बाद अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में लवलीना को 'फेयर चांस टीम% (देश छोड़ने के लिए मजबूर होने वाले खिलाड़ी) की सिंडी नगाम्बा ने 4-1 से हराया था। लवलीना ने विश्व चैंपियनशिप में देश के तीन पदक विजेता निकहत जरीन (स्वर्ण, 52 किग्रा), मनीषा मौन (कांस्य, 57 किग्रा) और परवीन हुड्डा (कांस्य, 63 किग्रा) के सम्मान समारोह के कार्यक्रम के इतर कहा कि मेरी तैयारी (विश्व चैंपियनशिप के लिए) इतनी अच्छी नहीं थी। ओलंपिक के बाद बहुत सी चीजें बदल गई हैं। मुझे कई चीजों को समय देना था, प्रतिबद्धताओं को पूरा करना था। उन्होंने कहा कि लेकिन जैसा कि एक कहावत है कि आप अपनी जीत से नहीं सीखते, आप अपनी हार से सीखते हैं और इस हार ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। भविष्य के लक्ष्यों के बारे में पूछे जाने पर असम की इस मुक्केबाज ने कहा कि मेरा मुख्य लक्ष्य अब भी ओलंपिक स्वर्ण है, लेकिन मुझे इसके लिए कदम दर कदम चलना होगा। ऐसे में मेरा अगला कदम राष्ट्रमंडल खेल है और मैं वहां चैंपियन बनना चाहती हूं।

गुजरात टाइटंस में मुझे सभी का समर्थन और खेलने का मौका मिला : मिलर

कोलकाता

डेविड मिलर टी20 क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। एक ऐसे फ़िनिशर की भूमिका जो गेंदबाज़ी ही नहीं करता। इस शैली के खिलाड़ियों को सफलता से अधिक निराशा हाथ लगती है। आपको विश्लेषकों को प्रभावित करने वाले बड़े रन बनाने का मौक़ा नहीं मिलता है। और तो और अगर आप विदेशी लीग में खेलते हैं, तो एकादश में स्थान बनाना कठिन हो जाता है। मिलर ने अपने पूरे करियर और विशेष रूप से अपनी पिछली फ़्रैंचाइज़ी में, जिसे हराकर उन्होंने आईपीएल 2022 के फ़ाइनल में जगह बनाई, इस बात को क़रीब से देखा है। इस सीज़न की शुरुआत से पहले मिलर ने ईएसपीएनक्रिकइंफ़ो के मैट रोलर को बताया था कि एक मुश्किल रोल में लगातार नहीं खेल पाना कितना निराशाजनक था।

साउथ अफ़्रीका के इस बल्लेबाज़ ने कहा था, (लगातार नहीं खेल पाना) निराशाजनक था। राजस्थान के पास अपने चार बड़े विदेशी खिलाड़ी हैं और वह उन्हीं पर टिके रहना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में लगातार नहीं खेल पाना मेरे लिए हताश करने वाला था। समय के साथ मैंने सीखा है कि टीम से बाहर होने पर मुंह फुलाने से

अच्छा है कि मैं अपने खेल पर काम करूं। बात टीम के इर्द-गिर्द सकारात्मक रहने की है। मैं नई टीम (गुजरात टाइटंस) को लेकर काफ़ी उत्साहित हूं। यह एक नई शुरुआत है और मैं वहां अपनी छाप छोड़ना चाहता हूं। वह राजस्थान रॉयल्स पर व्यंग्यात्मक तीर नहीं छोड़ रहे थे। जॉस बटलर, जोफ़्रा आर्चर और बेन स्टोक्स जब एकादश में हो तो टीम में जगह बनाना कतई आसान नहीं होता। मिलर किंग्स इलेवन पंजाब के लिए अपने पहले सीज़न में बनकर उभरे हिटर से एक संपूर्ण बल्लेबाज़ में विकसित हो चुके हैं। अपने पाले में मिलने वाली गेंदों को वह मैदान के बाहर भेजते थे लेकिन समय के साथ टी20 टीमों ने गेंद को उनके पाले से दूर रखना शुरू किया। इसके बावजूद आठ साल बाद अपने आईपीएल करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना काबिल-ए-तारीफ़ है। मिलर के अनुसार यह सब उन्हें मिले समर्थन का नतीजा है।

अपने करियर में आए इस बदलाव के बारे में पूछे जाने पर मिलर ने स्टार स्पोरट्स को बताया, सबसे पहले तो अवसर (मिलने लगे)। मुझे एक अच्छा रोल और टीम में मौक़े दिए गए। मुझे शुरुआत से ही समर्थन मिला। मैं अपने खेल का आनंद ले रहा हूं और पिछले कुछ वर्षों से मैं अपने खेल को और बेहतर तरीक़े से समझने लगा हूं। दबाव वाली स्थिति में आप कुछ अलग करने लगते हो लेकिन मैं अपने गेम प्लान के साथ चलने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि टीम को मिलर पर उनसे भी ज्यादा भरोसा था। हार्दिक पंड्या और टीम प्रबंधन के लिए मिलर नीलामी वाले दिन से ही एक मैच विनर थे। उन्होंने पता लगा लिया था कि इस खिलाड़ी को थोड़ा प्यार दिखाने की आवश्यकता है।

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात के कप्तान ने कहा, मुझे उनके खेल पर गर्व है। वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं और मुझे उनके साथ खेलकर गर्व महसूस होता है। मैं हमेशा चाहता था कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। यह दर्शाता है कि अगर आप किसी खिलाड़ी को प्रेम और महत्व देते हैं, वह कमाल कर सकता है। हार्दिक ने आगे कहा, कई लोगों ने मिलर को नज़रअंदाज़ कर दिया था लेकिन हमारे लिए वह हमेशा से एक मैच विनर थे। उन्होंने आज वही किया जिसकी हमें उम्मीद थी। यह ज़रूरी था कि हम उन्हें महत्व और प्रेम के साथ-साथ एक स्पष्ट भूमिका दें। अगर वह नाकाम भी होते हैं तो कोई बात नहीं, अंत में यह केवल एक मैच है।

सचिन तेंदुलकर का बेटे पर बयान

क्रिकेट से प्यार है तो मेहनत करो, मुंबई की टीम सिलेक्शन से मेरा कोई लेना-देना नहीं

नई दिल्ली

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे के क्रिकेट करियर को लेकर बड़ा बयान दिया है। सचिन का कहना है कि अर्जुन को इस खेल से बेशुमार मोहब्बत है, इसलिए वह क्रिकेट खेलता है। हालांकि, मैं उसे यही कहता हूं कि रास्ता मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल के दो सीजन में मुंबई इंडियंस के 28 मैच में एक बार भी खेलने का मौका नहीं मिला। बार-बार खबर आती रही कि अब अर्जुन को मौका मिल सकता है, लेकिन वह अवसर कभी नहीं आया। इसको लेकर अर्जुन के पिता सचिन ने बताया कि, उनका सिलेक्शन से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन वह हमेशा बेटे को समझाते हैं कि उनकी राह आसान नहीं बल्कि बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। 22 वर्षीय अर्जुन ने अपने करियर में अब तक घरेलू टीम मुंबई की ओर से सिर्फ दो टी-20 मुकाबले खेले हैं।

इस बार 30 लाख में बिके थे अर्जुन

मुंबई इंडियंस के साथ मेंटर के तौर पर जुड़े सचिन तेंदुलकर ने यह भी स्पष्ट किया कि वह चयन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। गौरतलब है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज अर्जुन को पांच बार के ड्डक्क चैंपियन मुंबई इंडियन्स ने अपने साथ जोड़ा था।

16 साल के प्रज्ञानानंद ने वर्ल्ड नंबर-10 गिरि को चौंकाया

चेसेबल मास्टर्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय, अब डिंग से सामना

नई दिल्ली

भारत के युवा ग्रैंडमास्टर रमेशबाबू प्रज्ञानानंद ने कमाल कर दिया है। वे शतरंज के बड़े-बड़े दिग्गजों को मात देते हुए चेसेबल मास्टर्स फाइनल में पहुंच गए हैं। अब उनका सामना वर्ल्ड नंबर-2 चीन के डिंग लिरेन से होगा। प्रज्ञानानंद चेसेबल मास्टर्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। महज 12 साल की उम्र में ग्रैंडमास्टर का टाइटल हासिल करने वाले प्रज्ञानानंद ने अपने से हाई रेटिंग वाले डच ग्रैंडमास्टर अनीश

गिरि को सेमीफाइनल मुकाबले में टाई ब्रेकर में 3.5-2.5 से हराया। इससे पहले चार गेम का मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा था। प्रज्ञानानंद ने इस प्रतियोगिता के 5वें दौर में विश्व चैंपियन मैगनस कार्लसन को हराया था। यह दूसरा मौका था, जब उन्होंने विश्व चैंपियन को पराजित किया था। इससे 90 दिन पहले फरवरी के महीने में उन्होंने एयरथिंग्स मास्टर्स में कार्लसन को पहली बार हराया था। इस प्रतियोगिता में प्रज्ञानानंद के अलावा दो और भारतीय खिलाड़ी शामिल थे। पी हरिकृष्णा और गुजराती इस 16 खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में शुरुआती आठ खिलाड़ियों में जगह नहीं बना पाए और नॉकआउट दौर में नहीं पहुंच सके।

हार्दिक की फील्डिंग पर स्टेडियम में ठहाकों की गूंज

बटलर का आसान सा कैच पकड़ने के दौरान फिसले, गेंद बाउंड्री पार

कोलकाता

राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2022 का पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला गया। गुजरात टाइटंस की टीम ने यह मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। इसी के साथ गुजरात ड्डक्क 15 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मैच के दौरान टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही राजस्थान की पारी के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। गुजरात की तरफ से यश दयाल पारी का 17वां ओवर लेकर आए। इस दौरान जोस बटलर बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर जोस ने बड़ा शॉट खेला और बॉल हवा में लॉन्ग ऑफ पर खड़े हार्दिक की ओर चली गई ।

सबको लगा कि हार्दिक जैसा दिग्गज फील्डर इतना आसान कैच किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। लॉन्ग ऑफ पर सिंपल कैच पकड़ने के लिए रेडी नजर

आ रहे हार्दिक का पैर फिसल गया। पांव फिसलते ही हार्दिक जमीन पर गिर पड़े। इधर गेंद ने आराम से टप्पा खाया और बाउंड्री के बाहर चली गई।

कैच के किस्से के बाद बटलर के चेहरे पर बिखरी मुस्कान

हार्दिक के इस कारनामें के बाद स्टेडियम ठहाकों से गूंज उठा। अब हार्दिक भी करते तो क्या करते। एक खिसियानी हंसी के जरिए अपनी गलती छिपाने का प्रयास किया। बटलर भी हंसने लगे। जोस बटलर इस कैच के छूटने तक टेस्ट इनिंग खेल रहे थे। कैच मिस होने के बाद जोस बिल्कुल बॉस की तरह खेलने लगे। पहले उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगा चुके बटलर ने 50 रन पूरा होने तक एक भी छक्का नहीं लगाया था। इसके बाद बटलर ने खेलने का अंदाज बदल दिया। 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बटलर 56 गेंदों पर 89 रनों की तूफानी पारी खेली।

SUPER HERO

यदि आप

किसी भी व्यक्ति को जानते हैं
जिसने, सामाजिक सरोकार में
असाधारण प्रदर्शन किया हो,
वह व्यक्ति आप स्वयं भी हो सकते हैं,
दोनों स्थिति में हमें पूर्ण विवरण, भेजें।

हम देश के असली नायक
SUPER HERO MP 2021
SUPER HERO IND 2021
खोज रहें हैं, उन्हें समाज, राष्ट्र के सामने लाना और
सम्मान दिलवाना, आपका-हमारा सयुंक्त प्रयास रहेगा।

Contact: Editorial Desk (Lifestyle),
ITDC News, 9826 220022
Email: responseitdc@gmail.com

PRESS ITDC ITDC NEWS
www.itdcindia.com

न्यूज ब्रीफ

निर्यात बैन के बावजूद गेहूं 1 रुपए भी सस्ता नहीं हुआ

नई दिल्ली। गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बावजूद इसकी कीमतों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। फैसले के 10 दिन बाद थोक भाव में मुश्किल से 15 से 75 रुपए प्रति क्विंटल की कमी आई है। रिटेल में यह कमी भी देखने को नहीं मिली है। इसके चलते रोटी समेत बिस्किट, ब्रेड, नूडल्स और अन्य बेकरी आइटम के दाम घटने की उम्मीद खत्म हो गई है। विशेषज्ञों की मानें तो गेहूं के दाम अभी और बढ़ेंगे। साल के अंत तक गेहूं 3,000 रु./क्विंटल तक जा सकता है। देश में गेहूं के दाम 2,300 रु./क्विंटल पहुंचने के बाद 13 मई को केंद्र ने गेहूं का निर्यात रोक दिया था। मकसद गेहूं की कीमतों में कमी लाना था। फैसले के तुरंत बाद तो गेहूं के दाम 4 से 8 फीसदी टूट गए, लेकिन नए हफ्ते से ही कीमतों में वापस तेजी आ गई। फिलहाल, गेहूं के दाम निर्यात प्रतिबंध वाले दिन के स्तर से 15 से 75 रुपए प्रति क्विंटल कम हैं।

सरकारी स्टॉक में 42 फीसदी गिरावट:- वेयर हाउसिंग और एग्रीफिनटेक कंपनी ओरिगो ई-मंडी के एजीएम तरुण सत्संगी ने कहा कि गेहूं की कीमतों में कमी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। इस साल गेहूं का उत्पादन कम होने के साथ ही सरकारी स्टॉक में 42 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल की तुलना में ओपेन मार्केट सेल स्कीम के तहत सरकारी गेहूं की बिक्री में भी गिरावट रहेगी। ऐसे में खुले बाजार में गेहूं की मांग बनी रहेगी। इधर, देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक करीब-करीब बंद हो चुकी है। जिन व्यापारियों ने ऊंचे दाम पर गेहूं खरीद रखा है, वे नुकसान में बिक्री नहीं करेंगे। ऐसे में मांग और आपूर्ति का समीकरण बिगड़ने से गेहूं के दाम बढ़ने लगेंगे। सत्संगी के मुताबिक, नई सप्लाई के पहले तक गेहूं का भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर को पार कर सकता है।

टैक्सबडी ने वित्तपोषण राउंड में जुटाए 21 लाख डॉलर

नई दिल्ली। ऑनलाइन कर परामर्श देने वाली कंपनी टैक्सबडी डॉट कॉम ने बुधवार को बताया कि संयुक्त अरब अमीरात स्थित जेनिथ ग्लोबल द्वारा आयोजित वित्तपोषण कवायद में उसने 21 लाख डॉलर (करीब 16 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी सुजीत बांगड़ ने यह कंपनी 2019 में शुरू की थी जिसमें स्वचालन प्रौद्योगिकियों का उपयोग परामर्श देने के लिए किया जाता है। कंपनी ने एक बयान जारी करके कहा कि इस कोष का उपयोग प्रौद्योगिकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि उसके मंच पर 4.5 लाख उपयोगकर्ता हैं। जेनिथ इससे पहले भी कंपनी में निवेश कर चुकी है, 2020 में उसने इसमें पहली बार 10 लाख डॉलर का निवेश किया था।

सीरम नवंबर में उतारेगी सर्वाइकल कैंसर का टीका

नई दिल्ली

देश में तैयार किया गया सर्वाइकल कैंसर टीका नवंबर तक उपलब्ध हो सकता है। दरअसल पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) अपने क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमावायरस (क्यूएचपीवी) टीके को लॉन्च करने के लिए कमर कस रही है। सूत्रों के मुताबिक, कंपनी ने अपने जोखिम पर स्टॉक तैयार करना शुरू कर दिया है हालांकि उसे देश के दवा नियामक से मंजूरी का भी इंतजार है। फिलहाल, भारत के पास बाजार में उपलब्ध एचपीवी टीके हैं लेकिन ये सभी विदेशी निर्माताओं ने तैयार किए हैं मसलन मर्क द्वारा तैयार किए गए गार्डासिल, ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन का टीका सेर्वरिक्स आदि। इस जगह में एसआईआई के प्रवेश से कीमतों में काफी कमी आने की उम्मीद है। फिलहाल एचपीवी टीके की लागत 2,000-3,000 रुपये प्रति खुराक है। एसआईआई जल्द ही

नियामक से टीके की मार्केटिंग की मंजूरी मांगेगी। हालांकि, क्यूएचपीवी तैयार करने की प्रक्रिया में लगभग चार से पांच महीने लगते हैं इसलिए टीका निर्माता ने टीके बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। एक करीबी सूत्र ने कहा, %हमारा लक्ष्य नवंबर के करीब क्यूएचपीवी टीका लॉन्च करना है। यह निश्चित रूप से दवा नियामक की मंजूरी पर निर्भर करता है।% एसआईआई का क्यूएचपीवी टीका पैपिलोमा वायरस के कई सीरोटाइप से बचाव के लिए वायरस जैसे कणों (वीएलपी) तकनीक का इस्तेमाल करता है और कंपनी को उम्मीद है कि यह लगभग 90 प्रतिशत मानव पैपिलोमा वायरस के बचाव में मददगार साबित होगा। दिसंबर 2020 में एसआईआई द्वारा लॉन्च किए गए निमोनिया के टीके के बाद, एचपीवी टीका इसका पहला प्रमुख गैर-कोविड-19 टीका होगा। एसआईआई ने दिसंबर में अपने कोविशील्ड टीके का उत्पादन रोक दिया था। इसकी हर महीने 25 करोड़ टीके की खुराक तैयार करने की क्षमता है। इसे हाल ही में अपने कोविड-19 टीके कोवोवैक्स के लिए 12-17 वर्ष के बच्चों में इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है। एचपीवी के अलावा, एसआईआई जल्द ही मलेरिया का टीका भी लॉन्च करेगा। इसे उम्मीद है कि उसके मलेरिया के टीके का उत्पादन साल के अंत में शुरू हो जाएगा। एक सूत्र ने कहा, %यह अब अफ्रीका में तीसरे चरण के क्लीनिकल परीक्षण में शामिल है और 2023 तक इस टीके का लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। इसीलिए, एसआईआई में इस साल के अंत तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने आर21 / मैट्रिक्स-एम बनाने के लिए एसआईआई के साथ भागीदारी की है। एसआईआई लाइसेंस के बाद हर साल इस टीके की 20 करोड़ से अधिक खुराक की आपूर्ति करेगा। एसआईआई के प्रतिद्वंद्वी भारत बायोटेक (जीएसके के साथ साझेदारी के माध्यम से) और जायडस लाइफसाइंसेज भी मलेरिया के टीकों को बाजार में ला रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, 2020 में दुनिया भर में अनुमानित स्तर पर मलेरिया के 24.1 करोड़ मामले थे और 627,000 लोगों की मौत हुई। अफ्रीका के क्षेत्र में वैश्विक मलेरिया का बोझ असमान रूप से अधिक है जहां 95 प्रतिशत मलेरिया के मामले और मलेरिया से होने वाली 96 फीसदी मौत (2020 में) का आंकड़ा भी शामिल है। इस प्रकार, इस टीके की वैश्विक मांग अधिक होने की उम्मीद है।

महंगाई को रोकने सरकार का कदम

सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट पर 1 जून से लगाई रोक

घरेलू कीमतों में उछाल को रोकना इसका कारण

नई दिल्ली

सरकार ने चीनी के निर्यात पर 1 जून 2022 से पाबंदी लगा दी। घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। इस साल 31 अक्टूबर तक ये पाबंदी जारी रहने वाली है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके टॉप ग्राहकों में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और दुबई शामिल हैं।

इस साल 82 लाख मीट्रिक टन चीनर का निर्यात

बीते साल देश ने भारी मात्रा में चीनी का निर्यात किया है। पिछले साल 60 स्न्र्ञ्ज (लाख मीट्रिक टन) तक चीनी निर्यात का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन असल में 70 स्न्र्ञ्ज चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई। इसी तरह इस साल भी 82 स्न्र्ञ्ज चीनी शुगर मिल से एक्सपोर्ट के लिए भेजी जा चुकी है, वहीं 78 स्न्र्ञ्ज तो एक्सपोर्ट भी हो गई। इस साल का

चीनी निर्यात अब तक का सबसे ज्यादा माना जा रहा है।

कई देशों ने अलग-अलग चीजों पर लगाया बैन

यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद, फूड प्राइसेस आसमान छू रही हैं और दुनिया भर की सरकारों ने अपने देश में जरूरी चीजों की कीमत न बढ़े इसके लिए इन वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है। मलेशिया 1 जून से चिकन का एक्सपोर्ट रोकने जा रहा है। इंडोनेशिया ने हाल ही में अस्थायी रूप से पाम ऑयल पर प्रतिबंध लगाया था। भारत ने गेंहूं के एक्सपोर्ट को भी प्रतिबंधित कर दिया है। सर्बिया और कजाकिस्तान ने अनाज शिपमेंट पर कोटा लगाया है।

भारत के पास 16 मिलियन का सरप्लस

चीनी एक्सपोर्ट को सीमित करने की सरकार की योजना काफी ज्यादा एहतियात वाली लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीनी की घरेलू आपूर्ति प्रचुर मात्रा में है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार, भारत में इस सीजन में 35 मिलियन टन उत्पादन और 27 मिलियन टन की खपत होने की उम्मीद है। पिछले सीजन के लगभग 8.2 मिलियन टन के भंडार सहित 16 मिलियन का सरप्लस है।

खाने के तेल आयात पर कस्टम ड्यूटी और सेस खत्म

खाने के तेल की कीमतों को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस खत्म करने का ऐलान किया है। यह सेस अभी 5 फीसदी है। फैसले से खाने का तेल सस्ता होने की उम्मीद है। तेलों के आायात पर दी गई छूट 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। महंगाई में खाद्य तेल की प्रमुख भागीदारी है और पिछले तीन महीनों से खाद्य तेल के खुदरा दाम में 15 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

स्पाइसजेट पर साइबर अटैक

घंटों की देरी से उड़ीं फ्लाइट

» पिछले हफ्ते पेमेंट विवाद के चलते दिल्ली में रोके गए थे प्लेन

नई दिल्ली

स्पाइसजेट के सिस्टम पर मंगलवार, 24 मई की रात को रैनसमवेयर का अटैक हुआ। इससे उसकी उड़ानों से रिलेटेड ऑपरेशन सुस्त पड़ गए और सुबह की कई उड़ानें प्रभावित हुईं। एयरलाइन ने बुधवार को ट्विटर के जरिये यह जानकारी दी है। स्पाइसजेट के मुताबिक स्पाइसजेट के सिस्टम में बीती रात रैनसमवेयर अटैक की कोशिश हुई हैं और इससे आज सुबह की कुछ फ्लाइट्स लेट हो गईं। हमारी ढ्ढञ्ज टीम स्थिति को कंट्रोल और ठीक कर लिया है। अब उड़ानें नॉर्मल रूप से चल रही हैं। पिछले हफ्ते भी स्पाइसजेट फ्लाइट को दिल्ली में रोका गया था, इसके पीछे की वजह एविएशन कंपनी का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पेमेंट नहीं करना बताया गया था। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा था कि सॉफ्टवेयर में टेक्निकल खराबी से डेली होने वाले पेमेंट में देरी हो गई थी। इसके बाद ऑपरेशन नॉर्मल हो गया था।ष्ठ ने 2020 में स्पाइसजेट को कैश एंड कैरी के आधार पर प्लेन के ऑपरेशन की अनुमति दी है, क्योंकि एयरलाइन अपनी पुराने बकाया का पेमेंट समय पर नहीं कर पा रही थी।

जल्द फ्लाइट में ब्रॉडबैंड शुरू करने का दावा:- कुछ दिन पहले ही स्पाइस जेट ने बताया था कि उसे अपने प्लेन्स में जल्द ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू होने की उम्मीद है। उसकी वेबसाइट के मुताबिक, एविएशन कंपनी के फ्लीट में 91 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 13 मैक्सप्लेन और 46 पुराने वर्जन के बोइंग 737 एयरक्राफ्ट हैं। स्पाइसजेट ने बुधवार को कहा कि उसने स्विटजरलैंड की कंपनी क्रेडिट सुइस के साथ चल रहे विवाद में समझौता और सहमति शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं और निष्कर्ष निकाला है।

श्रीलंका की राह पर पाक : राजनीतिक संकट ने बिगाड़े हालात

आईएमएफँ से फंड नहीं मिला तो कर सकता है ग्लोबल डिफॉल्ट

कोलंबो

आतंक का पनाहगार देश पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोरी का रिकॉर्ड बना रहा है और राजनीतिक हालात लगातार अस्थिर। इससे उसकी इकोनॉमी रसातल में पहुंच गई है। हालात इतने बुरे है कि अगर उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (ढ्ढरूस्न) से बेलआउट पैकेज नहीं मिला

तो वह श्रीलंका की ही तरह ग्लोबल डिफॉल्ट कर सकता है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान के इतिहास में दूसरी बार ऐसा होगा। बेलआउट पैकेज को लेकर बुधवार को आईएमएफ के साथ दोहा में बातचीत हुई। अधिकारियों ने माना कि लोन के लिए पाकिस्तान को कई कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं जिसमें फ्यूल प्राइस बढ़ाना भी शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कार्यवाहक गवर्नर मुर्तजा सैयद ने मंगलवार को ब्लूमबर्ग टीवी के साथ एक इंटरव्यू में कहा, हमें विश्वास है कि हम फिनिश लाइन पर पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान आईएमएफ से 3 अरब डॉलर के बेलाउट की मांग कर रहा है। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 10.2 अरब डॉलर था। यह दो महीने के इंपोर्ट के लिए भी काफी नहीं है।

फिर रफ्तार भरने की तैयारी में हिंदुस्तान मोटर्स

कोलकाता

कार बनाने वाली पहली देसी कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स दूसरी पारी शुरू करने की कोशिश में है। एंबेसडर जैसी लोकपिय्र कार देने वाली यह कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र पर नजर रखते हुए एक प्रमुख यूरोपीय कंपनी के साथ साझे उपक्रम के लिए बात कर रही है। इस बारे में समझौता हो चुका है और जांच-परख जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जो 2-3 महीने में पूरी भी हो जाएगी। हिंदुस्तान मोटर्स के निदेशक उत्तम बोस ने बताया, शुरूआत में इस परियोजना के तहत दोपहिया वाहन पेश किए जाएंगे और उनके बाद चारपहिया आएंगे।% बात तो साझे उपक्रम के लिए चल रही है मगर वह कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स में हिस्सेदारी भी ले सकती है क्योंकि बोस ने इस बात से इनकार नहीं किया। मगर उन्होंने कहा कि इस समय बातचीत साझे उपक्रम पर ही केंद्रित है, जिसमें 51 फीसदी हिस्सेदारी हिंदुस्तान मोटर्स के पास होगी। मगर उन्होंने कहा कि शेयरधारिता पर चर्चा हो सकती है और कंपनी इसका आकलन करेगी।

नए वाहन पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा में हिंदुस्तान मोटर्स के कारखाने में ही बनेंगे। इस कारखाने में कामकाज 2014 में रोक दिया गया था। उसके बाद से वहां काम पूरी तरह ठप है। वित्त वर्ष 2022 के सालाना नतीजों पर कंपनी ने कहा कि प्रबंधन ने कम उत्पादकता, बढ़ती अनुशासनहीनता, रकम की किल्लत और उत्पादों की मांग में कमी के कारण 24 मई, 2014 से उत्तरपाड़ा कारखाने में काम रोकने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में स्थित कारखाने में 4 दिसंबर, 2014 को छंटनी कर दी गई थी। एंबेसडर कार उत्तरपाड़ा कारखाने में ही बनती थी, जिसे मॉरिस ऑक्सफर्ड की तर्ज पर बनाया गया था। मगर इस नामी ब्रांड की चमक घटने के साथ ही कारखाने में काम भी बंद हो गया। हिंदुस्तान मोटर्स कार बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी थी। इसकी बुनियादी सीके बिड़ला के दादा बीएम बिड़ला ने की थी। एक समय सरकारी अमले में यही कार चलती थी और 1970 के दशक तक 75 फीसदी बाजार पर इसी का कब्जा था। मगर 1983 में मारुति सुजूकी ने मारुति 800 कार उतारी , जिसके बाद एंबेसडर का जादू फीका पडने लगा। रिपोर्ट बताती हैं कि 1984 से 1991 के बीच एंबेसडर की बाजार हिस्सेदारी घटकर केवल 20 फीसदी रह गई। उसके बाद दुनिया भर की कार कंपनियां भारत चली आईं और एंबेसडर की राह पहले से भी मुश्किल हो गई। एंबेसडर ब्रांड 2017 में केवल 80 करोड़ रुपये में प्यूजो एसए के हाथ बेच दिया गया। हिंदुस्तान मोटर्स का नया साझा उपक्रम उत्तरपाड़ा में कंपनी के पास बची 295 एकड़ जमीन का इस्तेमाल करेगा। उत्तरपाड़ा में कंपनी के पास पहले 700 एकड़ जमीन थी मगर 2007 में उसने अतिरिक्त पड़ी 314 एकड़ जमीने के लिए श्रीराम प्रॉपर्टीज के साथ सौदा कर लिया। पिछले साल हीरानंदानी समूह ने लॉजिस्टिक्स और हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन खरीदने का सौदा हिंदुस्तान मोटर्स के साथ किया। बोस ने कहा कि हीरानंदानी समूह के साथ जमीन सौदे से मिली पूंजी कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त होगी। बाकी धन का इस्तेमाल ईवी और पुर्जों की परियोजना के लिए किया जा सकता है।

इंटीग्रेटेड ट्रेड डेव्हलप सेंटर न्यूज के लिए मालिक, मुद्रक एवं प्रकाशक राधिका वीरेंद्र, स्वामी- इंटीग्रेटेड ट्रेड डेव्हलपमेंट सेंटर इंडिया ईप्रेस द्वारा साई प्रिंटर्स, 91 जहांगीराबाद भोपाल से मुद्रित करवाकर, श्री परिसर, 23 पश्चिम निशातपुरा, डीआईजी बंगला, भोपाल से प्रकाशित। संपादक- राधिका वीरेंद्र।
आरएनआई क्र. MPHIN/2018/77221, फोन- 0755-42223334, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल होगा।)